



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53]
No. 53]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 1978/फाल्गुन 10, 1899
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 1978/PHALGUNA 10, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

बजट 1978-79

वित्त मंत्री का भाषण

28 फरवरी, 1978

भाग 'क'

महोदय,

मैं 1978-79 का बजट पेश करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ।

2. चालू वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था (इकॉनमी) की जो प्रवृत्तियाँ रही हैं उनकी विस्तृत जानकारी "आर्थिक समीक्षा" (इकॉनॉमिक सर्वे) में प्रस्तुत की जा चुकी है। अतः मैं उनका उल्लेख संक्षेप में ही करूँगा।

3. कार्यभार संभालते समय हमें मुद्रास्फीति (इन्फ्लेशन) की अत्यंत विस्फोटक स्थिति विरासत में मिली थी। 1976-77 के दौरान कीमतों में 12 प्रतिशत से भी ज्यादा वृद्धि हुई थी। वह एक ऐसा वर्ष था जब कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद (ग्रॉस नेशनल प्रॉडक्ट) में 2 प्रतिशत से भी कम की वृद्धि हुई थी और मुद्रा उपलब्धि में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस प्रकार 1977-78 का प्रारम्भ उस समय हुआ था जब कि अर्थव्यवस्था में नकदी अत्यधिक मात्रा में मौजूद थी जिससे फिर एक बार मुद्रास्फीति का नया दौर शुरू होने का डर था। वर्ष के पहले भाग में, हमारी सरकार ने जनता को दिए गए अपने वचनों को पूरा करने के लिए अतिवायं जमा योजना (कम्पल्सरी डिपोजिट स्कीम) को वापस ले लिया और 8.33 प्रतिशत के सार्वजनिक (स्टेट्यूटरी) बोनस को भी बहाल कर दिया। इन कारणों से निस्संदेह मांग का दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया। इस पृष्ठभूमि में, यह बड़ी खुशी की बात है कि चालू वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था का संचालन इस ढंग से किया गया

कि जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कीमतें न बढ़ें। सम्मानित सदस्यों को यह जानकारी प्रसन्नता होगी कि आणविक शोध कीमतों का सूचक अंक (इण्डेक्स) उस स्तर से नीचा है जो हमें पिछली सरकार से विरासत में मिला था।

4. कीमतों में इस प्रकार सापेक्षिक स्थिरता (रिलेटिव स्टेबिलिटी) बनाए रखने में जो सफलता मिली है उसका कारण यह था कि प्रति प्रबंध और मार्बेजनात्मक वितरण की सक्रिय नीति तथा मुद्रा और ऋण के संबंध में प्रतिबंधात्मक नीति का तत्परता के साथ पालन किया गया। सरकारी भंडारों से अनाज और चीनी का वितरण उदारतापूर्वक किया गया। देश में खाद्य तेल, कपास और कृत्रिम रेशों की कमी को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में इनका आयात किया गया। अनेक आवश्यक वस्तुओं का नियति विनियमित किया गया और उनके शुल्कों (एक्स्पॉर्ट इंप्यूटी) में समुचित परिवर्तन किए गए ताकि देश में उनकी उपलब्धता बढ़ाई जा सके। प्रशासनिक और मौद्रिक दोनों प्रकार के कदम उठाए गए ताकि स्ट्रेबाजी के लिए जमाखोरी न हो जा सके और दवा दुष्प्राभंश बाजार में आ जाए। इनके साथ ही पर्याप्त उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अनाज-अन्न कई वस्तुओं के संबंध में एक सक्रिय समर्थन-कार्यक्रम (मार्गट प्रोग्राम) अगताया गया। हम औचित्य-पूर्वक यह दावा कर सकते हैं कि आवश्यक वस्तुओं के संबंध में एकीकृत मूल्य और वितरण नीति विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

5. मुझे इस बात में और भी संतोष मिलता है कि कीमतों में सापेक्षिक स्थिरता उस स्थिति में रखी जा सकी जबकि अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार किया जा रहा था। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में चालू वर्ष में 5 प्रतिशत की संतोषजनक वृद्धि होगी जबकि इसकी तुलना में 1976-77 में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। कृषि उत्पादन में पिछले

साल बहुत ज्यादा गिरावट आ गई थी लेकिन आशा है कि इस साल वह उस सारी कमी को पूरा ही नहीं कर देगा बल्कि उससे उपर भी निकल जाएगा। वृक्षों में देवी विपत्तियाँ आ जाने के बावजूद भी, खाद्यान्न का उत्पादन पिछले साल के स्तर से 100 लाख मेट्रिक टन ज्यादा होने की आशा है। वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में भी पर्याप्त रूप से सुधार होने की आशा है।

6. यह सुपरिणाम कुछ तो अच्छे मौसम के कारण और बहुत कुछ सिंचाई की क्षमता में वृद्धि किए जाने और उर्वरकों (फर्टिलाइजर्स), कीटनाशक दवाओं तथा अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों के हस्तेमाल को बढ़ाए जाने की वजह से प्राप्त हुआ है। वर्ष के दौरान सिंचाई की क्षमता में 22.3 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हो जाएगी—यद्यपि किसी भी एक वर्ष में इतनी वृद्धि नहीं हुई है। आशा है कि उर्वरकों का हस्तेमाल 23 प्रतिशत बढ़ेगा और वह 42 लाख मेट्रिक टन के स्तर तक पहुँच जाएगा। उम्मीद है कि 1977-78 में अधिक फसल देने वाली किस्मों के बीजों का हस्तेमाल और ज्यादा बढ़ जाएगा और लगभग 350 लाख हेक्टेयर जमीन में इनका प्रयोग होने लगेगा; इस प्रकार पूर्ववर्ती वर्ष की अपेक्षा 20 लाख हेक्टेयर से भी अधिक वृद्धि होगी। इस तरह जाने वाले वर्षों में कृषि की और अधिक गतिशील वृद्धि के लिए अब एक स्पष्ट आधार बिद्यमान है।

7. भुगतान शेष (बैलेन्स ऑफ पेमेंट) की स्थिति बराबर मजबूत बनी हुई है। लेकिन निर्यात में वृद्धि की दर कम हो गई है। इसका कारण यह है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में प्रगति की दर धीमी रही है, संरक्षण देने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, कुछ वस्तुओं की कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट आई है और कुछ अन्य वस्तुओं की मांग ही नहीं रही है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने निर्यात प्रयत्नों में बिलाई न करें। हमें अपने निर्यात संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाने जाना चाहिए और विदेशों में भारतीय निर्यात की जो साख बनी है उसे और बढ़ाते रहना चाहिए और उसके साथ ही हमारे निर्यात की प्रतियोगितात्मकता में सुधार करते रहना चाहिए।

8. आयात में वृद्धि होने के बावजूद, देश की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि (फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स) में आगे और वृद्धि हुई है, क्योंकि विदेशों से बराबर रकमें प्राप्त होती रही हैं और व्यापार खाते में भी कुछ अधिशेष (सुरप्लस) रहा है। चूंकि प्रारक्षित निधि में संचित राशियों का मतलब है विदेश में उधार लेना, इसलिए प्रारक्षित निधि में से धनराशियाँ निकाल कर भारत जैसे निर्धन देश द्वारा आंतरिक विकास के लिए उनका उपयोग किया जाना चाहिए।

9. प्रारक्षित निधि में संचित राशियों का उपयोग करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं लेकिन उनमें बराबर वृद्धि होती रही है; इससे यही पता चलता है कि ये कदम पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए मैं एक नई सुविधा बनाने का प्रस्ताव करता हूँ जिसके अन्तर्गत सावधिक ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाएँ (टर्म लेंडिंग फाइनेन्शियल इन्स्टिट्यूशन्स) और सरकारी क्षेत्र के बैंक अनुमोदित परियोजनाओं की आयात लागत को पूरा करने के लिए उचित शर्तों पर रुपयों में वित्त-व्यवस्था करेंगे। यह वित्त-व्यवस्था रुपयों में की जाने वाली उस व्यवस्था के अलावा होगी जो कि शेष लागत को पूरा करने के लिए पहले से ही उपलब्ध कराई जा रही है। बैंकों का एक संघ बनाया जाएगा जो सावधिक ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा दिए गए वित्त की अनुपूर्ति करने के लिए ऋण बिया करेगा।

10. साथ ही मैं इस धारणा का भी निराकरण कर देना चाहता हूँ कि हमारी विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसे बिना किसी वास्तविक औचित्य के खर्च किया जा सकता है। कृषि उत्पादन में घट-बढ़ होते रहने से और हमारे आयात की कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव आने से हमारे भुगतान शेष में भी भारी घट-बढ़ होती रहती है, और विकसित देशों के समान हमारे पास प्रारक्षित निधि का कोई दूसरा साधन भी नहीं है। इसलिए हमारी

विकास नीति में फेर-बदल करने की क्षमता और लचीलापन रखने के लिए, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्रारक्षित निधि रहना आवश्यक है। अतः हमें अपनी विकास क्षमता को बढ़ाने के लिए समसदारी के साथ उसका उपयोग करना चाहिए और उसे व्यर्थ में नहीं उड़ा देना चाहिए।

11. चालू वित्तीय वर्ष में, औद्योगिक उत्पादन में 5-6 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है। यह निस्सन्देह 1976-77 में औद्योगिक उत्पादन में हुई वृद्धि के मुकाबले कम है। किन्तु इस बात को मानना पड़ेगा कि इस वर्ष वृद्धि की दर नीची रहने का कारण, काफी हद तक यह था कि बिजली की कमी रही, और बिजली की कमी होने का कारण यह था कि पिछले सालों में इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की उपेक्षा की गई थी। इसके अलावा, 1976-77 में लोहा और इस्पात तथा कोयला जैसे बड़े उद्योगों के उत्पादन में जो वृद्धि हुई उसका बहुतसा भाग अन्तिम मांग को पूरा करने की बजाय उनके अपने भंडारों में रख लिया गया। इसके विपरीत चालू वर्ष में, इन उद्योगों के भंडार में कमी हुई जो कि एक अच्छा लक्षण है।

12. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की वर्तमान दर से संतुष्ट नहीं हो सकते। हमें औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए कोषिण करनी होगी क्योंकि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा करने, कीमतों में स्थिरता बनाए रखने और भावी विकास के लिए बचतें जुटाने के काम में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है। सरकारी निवेश में, खास तौर से बिजली, कोयला, परिवहन और सिंचाई जैसी आधारभूत सुविधाओं में अधिक पूंजी लगाने से आवश्यक प्रोत्साहन मिल सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी बहुत जरूरी है कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार किया जाए और साधनों का कारगर ढंग से हस्तेमाल किया जाए।

13. उपभोक्ता वस्तु उद्योगों (कन्स्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज) की दशा में सुधार तब हो सकता है जब कि अधिक कुशल कार्य-चालन और आधुनिकीकरण के द्वारा लागत को घटाया जाए और पहले से अधिक व्यापक आधार पर मांग पैदा की जाए। कृषि क्षेत्र में पूंजी के निवेश (इन्वेस्टमेंट) और ग्रामीण विकास पर अधिक बल दिए जाने के फलस्वरूप ग्रामीण आय में वृद्धि हो जाने से बहुत से उद्योगों को लाभ पहुँचना चाहिए। इससे हमारी उस दुर्लभ धारणा की पुष्टि ही होती है कि ग्रामीण विकास ही भावी विकास-नीति का मूलधार होना चाहिए।

14. इस सम्बन्ध में निर्यात की भूमिका को भी कम महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए। निर्यात सम्बन्धी मांग ने ही इंग्लैंड, जर्मनी, लोहा और इस्पात, वस्त्र और चीनी जैसे उद्योगों को काफी हद तक सहारा दिया है। यद्यपि भारत जैसी महाद्वीपीय अर्थ-व्यवस्था में, केवल निर्यात के आधार पर विकास करने का तो प्रयत्न ही उपरिष्ठ नहीं होता फिर भी इस बात पर बल देने की जरूरत है कि उत्पादन और निवेश को सहारा देने के लिए निर्यात महत्वपूर्ण भूमिका भूषा कर सकता है। निर्यात की आमदनी में वृद्धि होते रहने से नीति निर्धारण के मामले में जो सापेक्षिक स्वतंत्रता और फेरबदल करने की क्षमता मिली है उससे निर्यात संयर्जन (एक्सपोर्ट प्रमोशन) के सतत अभियान का महत्व उजागर होता है।

15. चालू वर्ष के दौरान आर्थिक क्षेत्र में काफी प्रगति होने के बावजूद भी, बेरोजगारी और गरीबी की वृद्धिवादी समस्याएँ हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। इन दैत्याकार समस्याओं पर कोई गंभीर प्रहार करने के लिए एक वर्ष का समय बहुत थोड़ा होता है। पिछले साल हमने कृषि और सहायक सेवाओं, सिंचाई और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के लिए अधिक साधनों की व्यवस्था करके एक शुरूआत कर दी थी। हमें इसी मार्ग पर बढ़ते रहना होगा क्योंकि उत्पादन और रोजगार में आवश्यक वृद्धि होने में समय तो लगेगा ही। आयोजना तैयार करने, कार्यान्वयन संगठन बनाने, उपयोगी वस्तुओं की पूर्ति की व्यवस्था करने और बिजली का प्रबंध करने का काम लगातार जारी रखना होगा। विकास की इस सामान्य नीति का ब्योरा हमें उस समय मिलेगा जबकि अगले महीने नई 'ोजना' राष्ट्र को समर्पित की जाएगी।

16. कुछ मोटे निर्णय जो इस नीति के अंग होंगे, पहले ही लिये जा चुके हैं। सरकार ने अगले पांच वर्षों में 170 लाख हेक्टेयर भूमि की अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें से 90 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई बड़ी परियोजनाओं से और 80 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई छोटी परियोजनाओं से की जाएगी जिससे पानी के सतही और भूमिगत दोनों प्रकार के साधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सकेगा। इसके साथ ही, ऐसे प्रयत्न भी किए जाएंगे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस भावी क्षमता का और विद्यमान सुविधाओं का भी कारगर ढंग से इस्तेमाल किया जाए। बिजली और उर्वरक जैसे उद्योगों में और पूंजी लगाकर उपयोगी वस्तुएं अधिक मात्रा में उपलब्ध की जाएंगी। सरकार रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ कार्बनिक खादों के प्रयोग को भी बढ़ावा देगी जिससे कि लम्बे अरसे तक इस्तेमाल में आने के बाद भी जमीन की गुणवत्ता सुरक्षित रहे। सिंचाई क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को औरवार ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा।

17. देश के कई भागों में, खेती का बहुत सा रकबा ऐसा है जहाँ इस समय सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और भविष्य में भी वह सतही या भूमिगत पानी के पर्याप्त साधनों के अभाव में, सिंचाई की सुविधा से वंचित ही रहेगा। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की विषमताओं को और अधिक नहीं बढ़ने देना है तो इन इलाकों को भी समृद्ध बनाना होगा। इसलिए बारानी खेती के तरीकों की ओर पहले से बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे सभी मोटे अनाज (जवार-बाजरा आदि) और बहुत सी दालें, तेलहन और कपास ऐसी परिस्थितियों में ही उगाई जाती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उपज में वृद्धि कम होती है और पैदावार तथा कीमतों में भयंकर उतार-चढ़ाव आते हैं।

18. गरीबी और बेरोजगारी को मिटाने में, कृषि के साथ-साथ लघु उद्योगों और ग्रामोद्योगों को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। नई औद्योगिक नीति के विवरण में सरकारी नीति के इस उद्देश्य का समावेश किया गया है। उत्पादन के बड़े इलाके कुटीर और लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित रखे गये हैं और एक ऐसे उन्नत संगठन की रूपरेखा बनाई गई है जो उन्हें तेजी से प्रगति करने में सहायता देगा। इसी के साथ-साथ, हो सकता है कि इनमें से बहुत से उद्योग उनमें व्यापक तकनीकी सुधार किए बिना सक्षम न हों, इसलिए उनके लिए अनुसंधान कार्य आरम्भ करने और उन्हें तकनीकी सहायता देने की तत्काल आवश्यकता है। मैं सच्चे दिल से यह आशा करता हूँ कि सरकारी क्षेत्र के उद्यम और संगठित क्षेत्र के अन्य उपक्रम इस विधा में प्रयत्नशील होंगे।

19. इस वर्ष औद्योगिक अशांति काफी चिन्ता का विषय बनी रही है। आपातकालीन विनियमों शासन में पहले जो मजबूरी रही उसकी कुछ प्रतिक्रिया होना तो स्वाभाविक था। किन्तु यदि इस अशांति को कम किए बिना ज्यों का त्यों रहने दिया गया तो उससे उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि अतिरिक्त उपलब्धियों की उचित मांगों को पूरा किया जाना चाहिए फिर भी इनका निर्धारण, देश की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के संदर्भ में ही करना होगा। अतः यह आवश्यक है कि बेतन, आय और मूल्य नीति निर्धारित करने के लिए मार्गनिर्देश प्राप्त किए जाएं। इस नीति के बारे में मार्ग निर्देशों का सुझाव देने के लिए हमने एक अध्ययन दल नियुक्त किया है। उसकी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत की जाने वाली है। उत्पादन की हानि देश के हित में नहीं है। इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि श्रम, प्रबन्ध और सरकार सब मिलकर सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध स्थापित करने में सहयोग दें।

20. ऐसा प्रतीत होता है कि विकास के साधनों की उपलब्धता में पूंजी निवेश की आवश्यकता के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि विकास-भिन्न व्यय में तेजी से वृद्धि हुई है और साधनों का आधार कटता गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रशासनिक व्यय में एकदम कपात बरती जाए और समाज के विभिन्न वर्गों को, पर्याप्त आर्थिक औचित्य के बिना जो तरह-तरह की रियायत और सहायता दी जाती है उसे कम कर दिया जाए। हमें परियोजनाओं के बेहतर आयोजन और कार्यान्वयन के जरिये लागत संबंधी अधिक प्रभावोत्पादकता का

लक्ष्य अपने सामने रखना चाहिए। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्य-चालन में और भी सुधार किया जाना चाहिए जिससे कि उनके अधिषेध की राशियों से राजकोष में अधिक योगदान मिले।

21. कीमतों पर प्रतिकूल वबाव वाले बिना यदि निवेश-व्यय में वृद्धि करना है तो व्यक्तियों और निगमों की बचत में भी वृद्धि करने की तत्काल आवश्यकता होगी। ऐसा करने के लिए उन लोगों की जीवन-शैली में अधिक सावगी लाने की आवश्यकता होगी जो बचत कर सकते हैं; और निगमों के मामले में कार्य-कुशलता बढ़ाने और अनावश्यक व्यय में कमी करने की जरूरत होगी।

1977-78 के संशोधित अनुमान

22. 1977-78 के संशोधित अनुमानों में, आय और निगम करों से प्राप्त होने वाले राजस्व में बजट अनुमानों की अपेक्षा 36 करोड़ रुपए की कमी दिखाई गई है और संघ उत्पाद शुल्कों में बजट अनुमानों की अपेक्षा 140 करोड़ रुपए कम प्राप्त होने की संभावना है; इन दोनों शीर्षों के अन्तर्गत बजट अनुमानों में क्रमशः 2336 करोड़ रुपए और 4593 करोड़ रुपए की राशि दिखाई गई थी। इसका मुख्य कारण यह था कि कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि धीमी गति से हुई। दूसरी ओर, सीमा-शुल्क और व्याज-कर से बजट अनुमानों की अपेक्षा क्रमशः 52 करोड़ रुपये और 16 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त होने की आशा है; बजट अनुमानों में इन शीर्षों के अन्तर्गत क्रमशः 1728 करोड़ रुपए और 99 करोड़ रुपए की राशि दिखाई गई थी। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा निकाल देने के बाद, जो मूल बजट में अनुमानित रकम, यानी 1799 करोड़ रुपए का है, केन्द्र का कर राजस्व का हिस्सा बजट अनुमान से 100 करोड़ रुपए कम रहेगा।

23. बाजार ऋणों की राशि 1000 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों से 183 करोड़ रुपए ज्यादा होगी क्योंकि बैंकों के पास अधिक राशियां जमा हुई हैं। लेकिन विदेशी सहायता के रूप में जो निवल राशि प्राप्त हुई है वह 1052 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 275 करोड़ रुपए कम है। इसका कारण यह है कि अब जो सहायता मिल रही है उसमें से अधिकांश राशि परियोजना सहायता के रूप में होती है जिसका संवितरण स्वभावतः धीरे-धीरे होता है। कार्यक्रम सहायता, जो जल्दी से उपयोग में लाई जा सकती थी, हमारे भुगतान शेष की स्थिति में सुधार हो जाने से कम कर दी गई है।

24. वर्ष के दौरान सरकार ने जनता के अधिकांश वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए अनेक निर्णय लिये जिनके कारण बजट पर अतिरिक्त बोस पड़ा। किसानों की भलाई के लिए, वर्ष के दौरान धान और गेहूं की बसुली कीमत (प्रॉयोरमेंट प्राइस) में वृद्धि की गई किन्तु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये मुहैया कराने के लिए उनकी निगम कीमत (इणू प्राइस) नहीं बढ़ाई गई। इसके अलावा, पिछले साल अक्टूबर में यूरिया की कीमतों में 100 रुपये प्रति मेट्रिक टन की और कमी कर दी गई हालांकि आयातित उर्वरकों की लागत में वर्ष के दौरान काफी वृद्धि हुई और उर्वरकों के स्वदेशी निमाताओं की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से उनके लिए प्रतिधारण कीमतें (रिटेंशन प्राइसेज) काफी ज्यादा बढ़ा दी गई। उर्वरकों की कीमतें निर्धारित करने की इस नीति के कारण केन्द्रीय बजट से सहायता देनी पड़ती है जो कि उर्वरकों पर लगने वाले आयात और उत्पाद शुल्कों (एक्ससाइज इयूटीज) से प्राप्त होने वाले राजस्व से कहीं ज्यादा होती है।

25. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कई सुविधाएं दी गईं। वर्ष के दौरान उनको महंगाई भत्ते की अतिरिक्त फिस्त मंजूर की गई। सरकारी भविष्य निधियों पर व्याज की दर बढ़ा दी गई और जो अभि-दाता (सब्सक्राइबर) रकम नहीं निकालते उनके लिए प्रोत्साहन बोनस योजना को और ज्यादा उदार बना दिया गया। पेंशनभोगियों को भी सितम्बर, 1977 से राहत-राशि की एक और फिस्त मंजूर की गई। इन सुविधाओं और अन्य रियायतों के कारण कुल मिलाकर काफी व्यय हुआ।

26. आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय, जिसमें रक्षा व्यय शामिल नहीं है, 5436 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से संभवतः 118 करोड़ रुपए ज्यादा हो जाएगा। इस वृद्धि में से 84 करोड़ रुपए की वृद्धि नियमित संवर्धन के अन्तर्गत हुई है, जो खासतौर से 1976-77 की बची हुई अदायगियों के कारण और चालू वर्ष में नियतकालिकों को जल्दी से सहायता का भुगतान करने की पद्धति अपनाए जाने के कारण हुई। इस वृद्धि को छोड़कर, आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय को, पहले बताए गए अतिरिक्त बोझ के होते हुए भी, वस्तुतः मूल बजट की सीमाओं में ही रखा गया है इस प्रकार आयोजना-भिन्न व्यय में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देने की जो प्रवृत्ति पिछले कई सालों से चली आ रही थी उसमें एक स्वागतयोग्य परिवर्तन हुआ है। हम खर्च में ज्यादा से ज्यादा किरायायत करके और अधिकतम संभव सीमा तक अनावश्यक व्ययों को काट-छांट कर ऐसा कर सके हैं।

27. आयोजना-भिन्न पूंजी व्यय में कुछ अधिक परिवर्तन हुआ है। द्विपक्षीय सहायता व्यापार करारों के अन्तर्गत, विदेशों को दिए जाने वाले तकनीकी सहायता में 100 करोड़ रुपए की निवल वृद्धि हुई है। ये ऋण उस समय वापस अदा किए जाएंगे जबकि वाक में व्यापारिक अंशतुलन ठीक हो जाएगा। उर्वरकों के आयात पर 190 करोड़ रुपए अधिक खर्च होंगे। इसका एक कारण तो यह था कि वर्ष के अंतिम दिनों में आयात इकट्ठे हो गए थे और दूसरे, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि हो गई थी।

28. जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मालूम है, हमने वर्ष 1976 के लिए कामगारों को 8.33 प्रतिशत का न्यूनतम बोनस बहाल कर दिया है। पतन और गांदी कामगारों के साथ भी एक बेतन संबन्धी समझौता हुआ था जिसके अनुसार जनवरी, 1974 से बकाया की अदायगियां करनी पड़ीं। इनके कारण सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना पड़ा है। इस कारण और कुछ अन्य प्रतिकूल बातों की वजह से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बजट के माध्यम से दी जाने वाली सहायता में 113 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

29. रक्षा व्यय उतना ही, यानी 2752 करोड़ रुपए का रहा है जितना कि मूल बजट में रखा गया था।

30. संशोधित अनुमानों से पता चलता है कि पैट्रोलियम, उर्वरक, इस्पात और दूर संचार पर आयोजना-व्यय, बजट में निर्धारित राशि से काफी कम होगा। यह मुख्य रूप से मशीनरी और उपकरण की सुपुर्दगी के कार्यक्रम में और सिविल निर्माण कार्यक्रमों में गड़बड़ी हो जाने के कारण हुआ। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के कुछ उपग्रह प्रयोजनों से अधिक मात्रा में आंतरिक साधन पैदा कर सके और इसलिए उन्हें अपने आयोजना परिषद (प्लान आउटलेट) की वित्त व्यवस्था करने के लिए बजट के माध्यम से पहले से कम सहायता की जरूरत पड़ी।

31. दूसरी ओर, ग्रामीण विकास सहित कृषि के कुल परिव्यय में 12 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की संभावना है। स्वास्थ्य के आयोजना व्यय में भी 13 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी, इसका मुख्य कारण यह है कि मलेरिया उन्मूलन के कार्यक्रम को और तेज कर दिया गया है। नई योजनाएं चालू करने से और पहले से चली आ रही योजनाओं, खासतौर से इस्पात और विद्युत संयंत्रों से जुड़ी हुई योजनाओं के कार्य में तेजी साने से कोयला क्षेत्र के परिव्यय में 13 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

32. कुल मिलाकर, केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं का बजट संबंधी परिव्यय 3978 करोड़ रुपए की मूल बजट व्यवस्था से संभवतः 230 करोड़ रुपए कम होगा। जितनी गति से आयोजनागत परियोजनाओं पर व्यय हो रहा है उससे मुझे बिल्कुल संतोष नहीं है। जरूरत इस बात की है कि संगठन में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाए। आने वाले महीनों में इस प्रश्न पर और अधिक ध्यान देने का विचार है।

33. राज्यों की आयोजनाओं को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की राशि 2031 करोड़ रुपए होगी जबकि बजट में इसके लिए 1617 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। राज्यों को उनकी आयोजनाओं की वित्त

व्यवस्था की कमी को पूरा करने के लिए और हाल में अभीतपूर्व देनी विनियमितों से प्रभावित राज्यों को अग्रिम आयोजना सहायता देने के लिए 414 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि खर्च की गई।

34. पिछले साल जब मैंने बजट पेश किया था तब मैंने बजट में 84 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान लगाया था। यह अनुमान मैंने भारतीय रिजर्व बैंक से लिये जाने वाले 800 करोड़ रुपए के उधार को हिसाब में शामिल करते हुए यह मानकर लगाया था कि वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा प्रारंभित निधि में से धनराशियां निकाली जाएंगी। लेकिन प्रारंभित निधि में से धनराशि निकाल लेने की देश की क्षमता के बारे में मेरा अनुमान सच नहीं निकला। कृषि मैंने स्पष्ट रूप से यह वायदा किया था कि मैं भारतीय रिजर्व बैंक से उसी हालात में इस ऋण का इस्तेमाल करूंगा जब कि प्रारंभित निधि से धनराशियां निकाल ली जाएंगी, इसलिए अब मैं वह उधार नहीं लेना चाहता। अनुमान है कि अब कुल मिलाकर बजट का घाटा 975 करोड़ रुपए का होगा। यह एक बड़ी रकम दिखाई पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले मैं इस बात को स्पष्ट कर दूँ कि इस राशि में से 414 करोड़ रुपए की रकम प्रत्यक्ष रूप से उस अतिरिक्त सहायता की शोक्त है जो कि मुझे विश्वास होकर राज्यों को उनका घाटा पूरा करने के लिये देनी पड़ी थी। सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि मैंने उनका ध्यान राज्यों की पदमुक्त सरकारों की अदूर-दक्षिणापूर्ण वित्तीय नीतियों की ओर भी दिलाया था। इसके अतिरिक्त उन बहुत से राज्यों को मदद भी दी जानी थी जिनके यहाँ सुफानों और बावों से अत्यधिक क्षति पहुँची थी। इसके परिणामस्वरूप साधनों में काफी कमी हो गई। राज्यों की नई सरकारों को सहायता देना मेरा कर्तव्य था जिससे कि वे समुचित रूप से नए सिरे से काम शुरू कर सकें। ऐसा करने के वाक मैं उनसे उचित रूप से यह आशा कर सकता हूँ कि वे इसके बाद अपने कार्यों की व्यवस्था इस प्रकार से करेंगे कि उन्हें अनधिकृत रूप से ओवरड्राफ्ट लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। मैं यह साफ-साफ बतला देना चाहूंगा कि मैं इस अवस्था प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा।

35. दूसरी 190 करोड़ रुपए की एक बड़ी रकम उर्वरकों का आयात करने के लिए खर्च की गई है। इस प्रक्रिया से हमने वास्तव में, विदेशी मुद्रा को उर्वरकों के मुख्यवान भंडार में रूपांतरित कर दिया है और इस प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए हमने मुद्रा उपलब्धि में कोई वृद्धि नहीं की है। सम्मानित सदस्य यह देखेंगे कि हालाँकि यह घाटा देखने में बड़ा मालूम होता है परन्तु सरकार की पूर्ति-व्यवस्था तथा ऋण-नियंत्रण की दूरदर्शितापूर्ण नीतियों के कारण इसके सभी प्रकार के प्रतिकूल प्रभावों को काबू में रखा जा सका है और हमने इस वर्ष को बिना किसी मुद्रास्फीति के पूरा कर दिया है।

1978-79 के लिए बजट अनुमान

36. वर्ष 1978-79 की वार्षिक आयोजना उस समय तैयार की गई जब कि नई 'राष्ट्रीय योजना' को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ पांचवीं आयोजना समाप्त हो रही है और पहली अप्रैल 1978 से नई राष्ट्रीय योजना चालू हो जाएगी। योजना आयोग इस समय, परिवर्तित प्राथमिकताओं के अनुसार विकास की नई नीति तैयार कर रहा है। अगले महीने जब राष्ट्रीय विकास परिषद् इस पर विचार-विमर्श कर चुकेगी तब इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

37. सम्मानित सदस्य यह महसूस करेंगे कि आयोजन एक सतत प्रक्रिया है और किसी भी समय अनेकों ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम चालू रहते हैं जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। इसके अलावा, इनमें बहुत सी परियोजनाएं समाप्ति की ओर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं और इसलिए अगर उनसे समय पर फल प्राप्त करने हैं तो उनके लिए समुचित व्यवस्था करनी पड़ती है। इन्हीं बातों ने 1978-79 की आयोजनागत प्राथमिकताओं का फिर से क्रम निर्धारण करने की हमारी स्वतन्त्रता को सीमित कर दिया है। फिर भी मैं यह कहने का साहस कर सकता हूँ कि 1978-79 की वार्षिक आयोजना, जिस रूप में यह तैयार हुई है,

विकास की कृषि-प्रधान और रोजगार-बहुल नई नीति को अपनाने के वर्तमान सरकार के बायबे को प्रतिबिम्बित करती है।

38. वर्ष 1978-79 के लिए केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक आयोजनाओं का कुल परिचय, 1977-78 के 9960 करोड़ रुपए के मुकाबले, 11649 करोड़ रुपए का होगा। यह 17 प्रतिशत वृद्धि का शोचक है। इस परिचय में से कोई 10465 करोड़ रुपए पहले से खली आ रही योजनाओं पर खर्च होंगे। शेष में से 150 करोड़ रुपए नई विद्युत परियोजनाओं का श्रृंगणेश करने के लिए रखे गए हैं और 1034 करोड़ रुपए अन्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। उक्त राशि का 80 प्रतिशत भाग, यानी 828 करोड़ रुपए कृषि संबंधी और ऐसी अन्य योजनाओं के लिए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहायक होंगी।

39. वर्ष 1978-79 के केन्द्रीय बजट में 7281 करोड़ रुपए की राशि केन्द्रीय आयोजना के लिये और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं में सहायता देने के लिए रखी गई है। वर्ष 1977-78 के लिए यह राशि 5790 करोड़ रुपए की थी।

40. राज्यों की आयोजनाओं में और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं में, पहाड़ियों और आदिम जातीय क्षेत्रों की उप-आयोजनाओं में केन्द्रीय सहायता देने के लिए तथा उत्तर-पूर्व परिषद की और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को सहायता देने के लिए 2761 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बजट में केन्द्रीय आयोजना के लिए 4520 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आन्तरिक और अन्य साधनों को मिलाकर, 1978-79 की केन्द्रीय आयोजना, 1977-78 की 4939 करोड़ रुपए की आयोजना के मुकाबले, 5664 करोड़ रुपए की होगी। कुल मिलाकर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाएं, उनके अपने साधनों सहित, 5985 करोड़ रुपए की होंगी जब कि 1977-78 में ये आयोजनाएं 5021 करोड़ रुपए की थीं।

41. बहुत-से वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाएं कुल मिलाकर केन्द्रीय आयोजना से बड़ी होंगी। कुल मिला कर राज्यों की आयोजनाओं के परिचय में 19 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जब कि संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं में 27 प्रतिशत की वृद्धि होगी। दूसरी ओर, केन्द्रीय आयोजना में 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इससे कृषि, सिंचाई, विजली और ग्रामीण विकास के पक्ष में हमने आयोजन संबंधी प्राथमिकताओं का जो नया क्रम-निर्धारण किया है उसका पता चलता है क्योंकि ये सभी योजनाएं राज्यों की आयोजनाओं का प्रमुख अंग हैं; और इससे कुछ अंश तक इस परिवर्तन का भी पता चलता है कि आयोजन के मामले में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पहले से ज्यादा है। प्रत्येक राज्य की आयोजना में कृषि, पहले से खल रही बड़ी और वरमियानी सिंचाई की परियोजनाओं तथा बिजली परियोजनाओं की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। इन दो क्षेत्रों की अत्यावश्यक नई योजनाओं के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

42. कृषि और ग्रामीण विकास पर बल देने की हमारी नीति के अनुसार, 1978-79 में कृषि के लिए 1754 करोड़ रुपए का आयोजना परिचय रखा गया है; इस प्रकार इसमें 490 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। खासतौर से सिंचाई क्षेत्र विकास के परिचय को, जो 1977-78 में 49 करोड़ रुपए था, बढ़ाकर 1978-79 के लिए 82 करोड़ रुपए कर दिया गया है और केन्द्रीय आयोजना में छोटे किसानों के विकास अभिकरण (एजेंसी) के परिचय को 45 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1978-79 के लिए 115 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रायः सूखा ग्रस्त रहने वाले इलाकों के कार्यक्रम के परिचय को, जो 1977-78 में 51 करोड़ रुपए था, बढ़ाकर 1978-79 के लिए 76 करोड़ रुपए कर दिया गया है। महत्त्व विकास कार्यक्रम के लिए 1978-79 में 20 करोड़ रुपए रखे जा रहे हैं जबकि 1977-78 में उसके लिए केवल 6 करोड़ रुपए रखे गए थे।

43. नई आयोजन-नीति के अनुसार, खण्ड विकास आयोजनाएं एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे रोजगार की व्यवस्था करने के लिए एक बड़ा साधन होंगी। इस कार्यक्रम का ध्येय तैयार किया जा रहा है। इस बीच, मैंने इस कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ रुपए की सांकेतिक व्यवस्था कर दी है। जब इस कार्यक्रम का पूरा ध्येय मासूम हो जाएगा तब इस राशि को और बढ़ा दिया जाएगा।

44. ग्रामीण विकास की नई नीति के एक अंग के रूप में डेरा विकास के एक विनाल कार्यक्रम—ओपरेशन प्लड II—को चालू करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम से लोगों का पोषण-स्तर ऊंचा होगा। पहले दौर में इससे लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और इसके सक्षम सहायक धर्मों के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में भ्राय बढ़ेगी। इस परियोजना पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके कार्यान्वयन के लिए ग्रामी तैयारी की जा रही है लेकिन इस बीच कार्यक्रम-पूर्व के कुछ आवश्यक तत्वों पर कार्रवाई करने की स्वीकृति दे दी गई है ताकि कार्यक्रम का मुख्य काम समय पर शुरू किया जा सके।

45. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश का समुद्रतट बहुत विस्तृत है और मछियारी का काम करने वालों की संख्या भी बहुत बड़ी है, केन्द्रीय आयोजना में मीनक्षेत्रों के परिचय को, जो 1977-78 में 33 करोड़ रुपए था, बढ़ाकर 1978-79 में 61 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस प्रकार परिचय बढ़ा दिए जाने से बुनियादी आधारभूत सुविधाएं तो मजबूत होंगी ही, साथ ही रोजगार में भी वृद्धि होगी और मछुओं की भ्राय भी बढ़ेगी।

46. अपने पिछले बजट भाषण में मैंने बताया था कि ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास संबंधी व्यापक कार्यक्रम के एक अंग के रूप में, सब तरह के मौसम में काम देने वाली पट्टन सड़क बनाने और समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के काम को तेजी से पूरा करने की जरूरत है। वर्ष 1978-79 में राज्यों की आयोजनाओं में ग्रामीण सड़कों के परिचय को, जो चालू वर्ष में 85 करोड़ रुपए था, बढ़ाकर 115 करोड़ रुपए कर दिया गया है। गांवों में पानी की व्यवस्था करने के लिए 1978-79 में राज्यों की परियोजनाओं में 105 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी जब कि चालू वर्ष में इसके लिए 70 करोड़ रुपए रखे गए थे। इसकी अनुपूर्ति के लिए केन्द्रीय आयोजना में भी 60 करोड़ रुपए की एक विशेष व्यवस्था की गई है। इस प्रकार पिछले साल जो यह वचन दिया गया था कि गांवों में पानी की व्यवस्था और सड़कों के निर्माण के लिए अधिक धनराशि निर्धारित की जाएगी, वह पूरा कर दिया गया है। मैं तो और आगे बढ़कर राज्यों को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि यदि इन कार्यक्रमों को कारगर तरीके से कार्यान्वित किया गया तो मैं इन धनराशियों को और बढ़ाने के लिए भी तैयार रहूंगा।

47. मैंने पहले भी इस बात पर बल दिया था कि ग्रामोबांगों और लघु उद्योगों के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में लाभदायक रोजगार के अवसर बढ़ाने की जरूरत है। इन के लिए 1978-79 में कुल 219 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है जबकि 1977-78 में इनके लिए 145 करोड़ रुपये रखे गए थे।

48. अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्यक्रमों को अब विशेष प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि इनके परिचय को, जो 1977-78 में 86 करोड़ रुपए था, बढ़ाकर 1978-79 में 125 करोड़ रुपए कर दिया गया है। राज्यों की आयोजनाओं में आदिम जातियों के विकास के लिए परिचय को, जो 1977-78 में 258 करोड़ रुपए था, बढ़ाकर 1978-79 में 343 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा, आदिम जातियों से संबंधित उप-आयोजनाओं के लिए केन्द्र की ओर से जो विशेष सहायता दी जाती है वह भी बढ़ाकर 1978-79 में 70 करोड़ रुपए की जा रही है जबकि 1977-78 में इसके लिए 55 करोड़ रुपए रखे गए थे।

49. अगले पाँच वर्षों में 170 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता बनाने का जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके लिए पूँजी निवेश में भारी वृद्धि करनी होगी और आयोजन, निष्पादन तथा पर्यवेक्षण के लिए संगठनात्मक व्यवस्था को नया रूप देने, सुदृढ़ करने और सुचारु बनाने की आवश्यकता होगी। बड़ी और दरमियानी सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1978-79 में 1166 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा जबकि 1977-78 में इसके लिए 1032 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी। छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1978-79 में, 1977-78 के 206 करोड़ रुपये के मुकाबले, 235 करोड़ रुपये का आयोजना परिव्यय होगा। कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम से ऋण लेकर इस परिव्यय की काफी हद तक अनुपूर्ति की जाएगी। ग्रामों की जाती है कि 1978-79 में, 1977-78 के 22.3 लाख हेक्टेयर के मुकाबले, 30 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता का निर्माण किया जाएगा।

50. पिछले वर्षों में, बिजली के लिए अपर्याप्त धन-राशि नियत किये जाने और बिजली परियोजनाओं की धीमी गति से कार्यान्वित किए जाने की वजह से इस बुनियादी आधारभूत सुविधा में बराबर कमी महसूस की जाती रही है। यदि हम चाहते हैं कि बिजली की बार-बार होने वाली कमी की वजह से हमारी विकास की गति अवरोध न हो तो इन दोनों बातों में सुधार करना होगा। इसलिए 1978-79 की आयोजना में बिजली पैदा करने की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि करने और परीक्षण तथा वितरण व्यवस्था का विकास करने की परिकल्पना की गई है। आगामी वर्ष में कुल मिलाकर लगभग 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता का निर्माण करने की योजनाओं को विभिन्न चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें से लगभग 3,500 मेगावाट बिजली 1978-79 में पैदा की जाने लगेगी जबकि चालू वर्ष में लगभग 2,000 मेगावाट बिजली पैदा किय जाने का अनुमान था और इस तरह देश में बिजली पैदा करने की कुल क्षमता बढ़ कर 29,000 मेगावाट हो जाएगी।

51. केन्द्रीय क्षेत्र में कई परियोजनाओं, जैसे कोरबा उच्च स्तरीय तापीय परियोजना, रामगुडम उच्च तापीय परियोजना, नेवेली स्थित द्वितीय खान कटाव समेत बिजली-घर, बदरपुर तापीय बिजली घर-सीसरा चरण, दामोदर घाटी निगम के बोकारो तापीय बिजली-घर और पश्चिम पहाड़ी के उद्वाहित संग्रहण संयंत्र (पम्पड स्टोरेज प्लांट) में नया काम शुरू करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। उच्च तापीय बिजली-घरों में से संघर्ष केन्द्रीय क्षेत्र में तथा राज्यों में 400 के० की० की नई परीक्षण लाइनों का काम हाथ में लेने के लिए भी व्यवस्था की गई है। भार प्रेषण केन्द्रों के काम की रफ्तार भी तेज की जा रही है। इससे सदन की बिजली पैदा करने के उस कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिल जानी चाहिए जिसे हम हाथ में लेने जा रहे हैं।

52. बिजली के विकास के लिए केन्द्रीय आयोजना में 244 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। बिजली के लिए अधिकांश व्यवस्था राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं में की गई है जहाँ इसके परिव्यय के लिए कुल 1953 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। बिजली के क्षेत्र के लिए 1978-79 में 2217 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि चालू वर्ष में इसके लिए 1925 करोड़ रुपये की रकम रखी गई थी। ग्रामीण विद्युतीकरण के महत्व को देखते हुए इसके लिए व्यवस्था को बढ़ा कर 297 करोड़ रुपये कर दिया गया है जबकि चालू वर्ष में इस प्रयोजन के लिए 195 करोड़ रुपये रखे गए थे। हम इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे कि इन परियोजनाओं को शीघ्रता तथा कुशलता से कार्यान्वित किया जाए ताकि इतनी भारी मात्रा में लगाई गई पूँजी से अर्थव्यवस्था को पूरा पूरा लाभ पहुँचे।

53. तेल के क्षेत्र के लिए 1978-79 में 630 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है क्योंकि कच्चे तेल के मामले में आत्मनिर्भर बनने के हमारे प्रयासों में कोई छिलाई नहीं आनी चाहिए। यह दूसरा कदम है जो राष्ट्र ने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठाया है।

54. इस्पात के लिए 1978-79 के बजट में 563 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है, जबकि 1977-78 में 511 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। चिल्लाई और बोकारो के विस्तार कार्यक्रमों, राऊरकेला के कोल्ड रोड ग्रेन ओरिएण्टेड प्लांट और सेलम इस्पात संयंत्र की आवश्यकताएँ पूरी कर दी गई हैं। कुद्रेमुख परियोजना के परिव्यय को, 1977-78 के 142 करोड़ रुपये से बढ़ाकर, अगले वर्ष में 213 करोड़ रुपये किया जा रहा है ताकि परियोजना को सुनिश्चित समय पर पूरा किया जा सके।

55. इस तरह की धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है कि यह सरकार परिवार नियोजन के कार्य को कम महत्व दे रही है। इस प्रकार की धारणा बिल्कुल गलत है। परिवार नियोजन के ज़ोरदार तथा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का हमारा वायवा पक्का और साफ है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 1978-79 में 393 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है जबकि 1977-78 में इस प्रयोजन के लिए केवल 284 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। अब इस बात को महसूस किया जा रहा है कि परिवार नियोजन के संकुचित पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करने की बजाय, परिवार कल्याण की व्यापक संकल्पना को अपनाने से परिवार नियोजन की पद्धतियों को ज्यादा अच्छी तरह से स्वीकार किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए भी, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों की योजना भी शामिल है, केन्द्रीय आयोजना तथा राज्यों की आयोजना में पर्याप्त मात्रा में धनराशि की व्यवस्था कर दी गई है।

56. यह सरकार इस तथ्य को पूर्ण रूप से मान्यता देती है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था के प्राथमिकीकरण में और कृषि तथा उद्योग के विकास में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को मूल्यवान योगदान देना है। सम्मानित सदस्यों का यह जानकर प्रसन्नता होगी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के परिव्यय को, जो 1977-78 में 179 करोड़ रुपये था, बढ़ाकर 1978-79 में 220 करोड़ रुपये कर दिया गया है, अर्थात् उसमें 23 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के लिए व्यवस्था को, 1977-78 के 37 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1978-79 में 51 करोड़ रुपये कर दिया गया है। भारतीय उपग्रह परियोजना (इंस्टे-1), जिसके संबंध में 1978-79 में 23 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह परियोजना इस अर्थ में अद्वितीय है कि इसमें दूर-संचार, ऋतु विज्ञान तथा दूरदर्शन की अनेक सुविधाएँ एक साथ रखी गई हैं।

57. अनुमान है कि रक्षा-संबंधी व्यय को छोड़कर आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय 5908 करोड़ रुपये का होगा, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 354 करोड़ रुपये ज्यादा है। ब्याज की भ्राम्यगियों तथा ऋणों का दिने जाने वाले अनुमानों की वजह से कुल मिलाकर 384 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। यदि हम इन दोनों मदों को शामिल न करें, तो अन्य आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय, चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से कम बैठेगा। आयोजना-भिन्न व्यय पर कड़ी निगरानी रखने से और अधिक से अधिक किरायेत करने के उद्देश्य से उसमें काट-छांट करने के कारण यह संभव हुआ है। सहायता के रूप में जो विभिन्न प्रकार की अदायगियाँ की जाती हैं, वे वर्तमान आर्थिक स्थिति में कितनी प्रसंगानुसूल रहनी इस बात को ध्यान में रखते हुए उनकी समीक्षा की गई है और तत्संबंधी व्यवस्थाओं को समुचित रूप से कम कर दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को, बजट के जरिये जो आयोजना-भिन्न सहायता दी जाती है उसमें भी चालू वर्ष की अपेक्षा 127 करोड़ रुपये की कमी की जा रही है।

58. अगले वर्ष में रक्षा व्यय, चालू वर्ष के 2752 करोड़ रुपये के मुकाबले 2945 करोड़ रुपये होगा।

59. अनुमान है कि कराधान की वर्तमान दरों पर 1978-79 में, 9636 करोड़ रुपये का सकल कर-राजस्व प्राप्त होगा जो चालू वर्ष

के संशोधित अनुमान से 730 करोड़ रुपये अधिक है। आशा है कि आय तथा निगम-कर से प्राप्त होने वाले राजस्व में कमशः 115 करोड़ रुपये तथा 145 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। अनुमान है कि संघ उत्पाद-शुल्कों से 374 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त होंगे। सीमा-शुल्कों से प्राप्त होने वाले राजस्व में भी 70 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, जो 1929 करोड़ रुपये का है, पहले से 130 करोड़ रुपये ज्यादा होगा।

60. बाजार ऋणों से 1650 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी जबकि चालू वर्ष में 1183 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है। मूल रकम की वापसी और व्याज की प्रदायगी की व्यवस्था करने के बाद, 1138 करोड़ रुपये की निवल विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान है। इस राशि में नए ऋणों के आधार पर प्राप्त भुगतान भी शामिल हैं।

61. अन्य प्राप्तियों को हिसाब में लेने के बाद, 1978-79 में कुल मिलाकर 17021 करोड़ रुपये की प्राप्ति होने का अनुमान है। अगले वर्ष में कुल व्यय 18417 करोड़ रुपये का होगा। इस तरह से कराधान की वर्तमान वरों पर बजट में कुल घाटा 1396 करोड़ रुपये का रहेगा। सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि सरकार ने कल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पहली जनवरी, 1978 से मंहगारी भत्ते की एक और किस्त देने के अपने निर्णय की घोषणा की थी। चीनी उद्योग के संबंध में सरकार की नई नीति भी कल घोषित की गई थी। इन दोनों निर्णयों के कारण अगले साल केन्द्रीय राजकोष पर 80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। जाहिर है कि मैं इस व्यय को अपने बजट प्रस्तावों में शामिल नहीं कर सका हूँ। तथापि मुझे आशा है कि यह अतिरिक्त व्यय कृषियत के उन उपायों से, जिनके कार्यान्वयन में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है, काफी हद तक बजट अनुमानों के भीतर ही पूरा किया जा सकेगा।

MINISTRY OF FINANCE

BUDGET 1978-79

Speech of Minister of Finance

28th February, 1978

PART 'A'

Sir,

1. I rise to present Budget for the year 1978-79.

2. The Economic Survey has presented a detailed review of the trends in the Indian economy for the current year. I shall, therefore, refer only briefly to them.

3. We inherited a highly explosive inflationary situation when we took office. Prices in 1976-77 went up by over 12 per cent. In a year in which real gross national product increased by less than 2 per cent, money supply went up by 20 per cent. Thus at the beginning of 1977-78, the economy was faced with a massive excess of liquidity which threatened to unleash a fresh bout of inflation. In the early part of the year, our Government, in the process of honouring its commitments made to the people, withdrew the compulsory deposit scheme and also restored the statutory bonus of 8.33 per cent. These measures no doubt further added to the pressure of demand. Against this background, it is most gratifying that the economy has been so managed during the current year as to ensure that prices did not increase. Hon'ble Members will be pleased to note that the wholesale price index is today lower than the level inherited by us from the previous Government.

4. This relative price stability has been achieved by pursuing an active policy of supply management and public dis-

tribution and a policy of restriction on money and credit. The issue of cereals and sugar from the public stocks has been liberal. Large quantities of edible oil, cotton and artificial fibres were imported to make up domestic shortfalls. Exports of a number of essential commodities were regulated and export duties were adjusted in order to increase domestic availability. Both administrative and monetary steps were taken to ensure that speculative hoarding did not take place and cornered stocks came on to the market. At the same time an active support programme was pursued with regard to many commodities other than cereals to ensure incentives for adequate production. We can justifiably claim that significant progress was made towards evolving an integrated price and distribution policy for essential commodities.

5. I derive added satisfaction from the fact that relative price stability has been maintained against the background of a rapidly expanding economy. The gross national product will register a satisfactory growth of 5 per cent in the current year as compared to 1.6 per cent in 1976-77. Agricultural production which had declined sharply last year is expected to more than make up the lost ground. Foodgrain production is expected to exceed last year's level by about 10 million tonnes despite the natural disasters in the South. The production of commercial crops is also expected to improve considerably.

6. This result has been achieved in part due to good weather but to an even greater extent because of the increased irrigation potential, increased use of fertilizers, pesticides and high yielding variety seeds. Additional irrigation potential created during the year will be 2.23 million hectares—the highest achieved in a single year so far. The use of fertilizers is expected to go up by 23 per cent to 4.2 million tonnes. The area under high yielding variety seeds is expected to increase to nearly 35 million hectares in 1977-78, an increase of more than 2 million hectares over the previous year. Clearly the basis now exists for a more dynamic growth of agriculture in the years to come.

7. The balance of payments continues to be strong. Export growth has, however, slowed down considerably. Slow growth of the world economy, growing protectionism, a sharp decline in some commodity prices and a lack of demand for others account for this. It is important, therefore, that we do not relax in our export efforts. We should indeed continue to strengthen the export organisation that has been built up and the image of Indian exports that has been created while simultaneously improving the competitiveness of our exports further.

8. The country's foreign exchange reserves have risen further, despite an increase in imports, because of continued inward remittances and a small surplus on trade account. Since reserve accumulations amount to lending abroad, these should be drawn down and used for internal development by a poor country like India.

9. A number of steps have been taken to utilise these reserves but the continued accretion indicates that these are not enough. I, therefore, propose to create a new facility under which term lending financial institutions and public sector banks will provide rupee finance on appropriate terms to cover the import costs of approved projects. This will be in addition to the rupee finance which is already being made available to cover domestic costs. A consortium of banks will be formed to provide such loans, supplementing the finance by the term lending institutions.

10. At the same time, I want to dispel the impression that our reserves are so large that they have to spent without any real justification. The fluctuations in our balance of payments arising from swings in agricultural production and in the prices of some of our essential imports are large, and we do not have a secondary line of reserves as the developed countries have. A substantial volume of reserves is thus necessary for us to have manoeuvrability and flexibility in our development policy. We should, therefore, use them wisely to increase our development potential and not fritter them away.

11. Industrial production in the current fiscal year is expected to show an increase of 5-6 per cent. This is no doubt less than the growth of industrial production in 1976-77. However, it has to be recognised that the lower growth rate this year is to a large extent due to the shortage

of power which is directly attributable to the past neglect of this vital sector. Besides, a substantial part of the increased output of major industries in 1976-77, such as iron and steel and coal went into inventories rather than in satisfying final demand. By contrast, inventories in these industries have shown a healthy decline in the current year.

12. It goes without saying that we cannot be satisfied with the present rate of growth of industrial production. We must strive for acceleration in industrial growth since it can make a material contribution in generating new employment opportunities, maintaining price stability and providing savings for future growth. An increase in public investment, particularly in infrastructural facilities such as power, coal, transport and irrigation can provide the necessary fillip. In addition, there is an urgent need to improve project implementation and make an effective use of resources.

13. An improvement in the state of consumer goods industries depends upon cost reduction through more efficient operation and modernisation and on generation of a more broadbased demand. An increase in rural incomes resulting from the increased emphasis on agricultural investment and rural development should prove beneficial to a wide range of industries. This only reinforces our conviction that rural development should constitute the heart of the future strategy of growth.

14. The role of exports should not be underestimated in this regard. Export demand has sustained to a significant extent industries like engineering, leather, iron and steel, textiles and sugar. Though in a continental economy like India export led growth may be out of question, the important role which exports can play in sustaining production and investment needs to be emphasised. The relative freedom and manoeuvrability which growing export earnings have given to policy making underscore the importance of a sustained export drive.

15. In spite of the considerably better economic performance during the current year, the basic problems of unemployment and poverty continue to be with us. A year is too short a period to make any serious impression on these gigantic problems. We made a beginning last year by allocating more resources to agriculture and ancillary services, irrigation and rural infrastructure. We will have to persist along these lines because it is only over time that the necessary increase in output and employment will come about. The effort to plan, build an implementation organisation, arrange supply lines of inputs and marketing will have to go on unrelentingly. The details of this general strategy of development will be available to us when the new Plan is presented to the nation next month.

16. Certain broad decisions which will be part of this strategy have already been taken. Government have formulated a target of creating an additional irrigation potential of 17 million hectares in the next 5 years. Nine million hectares will be under major irrigation and 8 million hectares will be under minor irrigation so that an optimal use will be made of both surface and ground-water resources. Simultaneously efforts will be made to ensure that this potential as well as existing facilities are used effectively. The supply of inputs will be increased through investment in industries like electricity and fertilizers. Government will also promote the use of organic manures along with chemical fertilizers to protect the quality of the soil over the long run. Command area development programmes will be implemented vigorously.

17. In many parts of the country a large proportion of the area under cultivation is without irrigation at present and it will be without irrigation in the future as well because of lack of adequate surface or ground water resources. These areas also have to prosper if rural disparities are not to widen. Therefore much more attention will have to be paid to dry cultivation methods. This is extremely important because all of our millets, and a large proportion of pulses, oilseeds and cotton are grown under such conditions, leading to low growth of output and violent fluctuations in output and prices.

18. Along with agriculture small industries and rural industries have an important part to play in the elimination of poverty and unemployment. The new Industrial Policy Statement embodies this goal of government policy. Large areas of production have been reserved for cottage and

small industries and an improved organisation which will help them grow faster has been outlined. At the same time, since many of these industries may not be viable without a great deal of technical improvement, there is an urgent need to undertake research and render technical assistance to them. I earnestly hope that efforts in this direction will be made by public sector enterprises and others in the organised sector.

19. Industrial unrest has been causing a great deal of anxiety this year. A certain reaction to the earlier constraint under the obnoxious emergency regime is understandable. But output is likely to be affected seriously if this unrest is allowed to continue unabated. While the legitimate demands for additional emoluments should be met, these have to be appraised against the socio-economic realities of the country. It is, therefore, important to have guidelines to determine a wages, incomes and prices policy. We have appointed a study group to suggest guidelines for such a policy. Its report is due to be submitted shortly. A loss of production is not in the interest of the country. It is, therefore, of the utmost importance that labour, management and government cooperate in bringing about harmonious industrial relations.

20. The availability of resources for development does not seem to have kept pace with the need for investment. This is because of the rapid increase in non-development expenditure and the erosion of the resource base. Therefore, it is necessary to practise the utmost economy in administrative expenditure and to curtail the various concessions and subsidies given to different sections of society without adequate economic justification. We should aim at greater cost effectiveness through better project planning and implementation. The working of public sector projects should be improved still further so that their surpluses contribute more to the public exchequer.

21. There is also an urgent need to increase individual and corporate saving if increased investment expenditure is to take place without any adverse pressures on prices. This would require greater simplicity in the life style of those individuals who can save, and a greater efficiency and a reduction in inessential expenditure on the part of corporations.

Revised Estimates for 1977-78

22. In the Revised Estimates for 1977-78, the revenue from income and corporation taxes shows a shortfall of Rs. 36 crores and Union excise duties are expected to yield Rs. 140 crores less than the Budget Estimates of Rs. 2336 crores and Rs. 4593 crores respectively. This is mainly due to the slower growth of industrial production in certain sectors. The yield from customs revenues and the interest-tax, on the other hand, is expected to show an improvement of Rs. 52 crores and Rs. 16 crores over the Budget Estimates of Rs. 1728 crores and Rs. 99 crores respectively. After allowing for States' share of taxes and duties, which remains at Rs. 1799 crores as in the original Budget, Centre's share of tax revenue will be less than the Budget estimate by Rs. 100 crores.

23. Market loans will exceed the Budget figure of Rs. 1000 crores by Rs. 183 crores, because of larger deposit accretions with banks. But net receipts on account of external assistance will be lower than the Budget Estimate of Rs. 1052 crores by Rs. 275 crores. This is due to the fact that a larger proportion of aid received now is project aid which is by nature slow disbursing. Programme assistance, which would have been utilised quickly, has been reduced because of the improvement in our balance of payments.

24. During the course of the year a number of decisions taken by Government for the benefit of large sections of the population cast additional burdens on the Budget. To benefit farmers, the procurement prices of paddy and wheat were increased during the year without raising the issue prices from the public distribution system. Again, urea prices were further reduced by Rs. 100 per tonne in October last year, though in the course of the year the cost of imported fertilizers increased significantly and the retention prices to domestic manufacturers of fertilizers were raised to improve their viability. This policy of pricing fertilizers involves a subsidy from the Central Budget which is much more than the revenue from import and excise duties on fertilizers.

25. A number of benefits were given to Central Government employees. An additional instalment of dearness allowance was sanctioned to them during the year. The rate of interest on Government provident funds has been enhanced

and the incentive bonus scheme for those subscribers who do not make withdrawals has been further liberalised. The pensioners too were sanctioned another instalment of relief from September, 1977. These and other concessions given add up to a substantial expenditure.

26. Non-Plan revenue expenditure, excluding Defence, is likely to exceed the Budget Estimate of Rs. 5436 crores by Rs. 118 crores. Of this increase, Rs. 84 crores is under export promotion, due mainly to a spill over of payments pertaining to 1976-77 and the introduction in the current year of a system of quicker disbursement of assistance to exporters. Barring this increase, non-Plan revenue expenditure has been kept practically within the original Budget despite the additional burdens already mentioned. This is a welcome departure from the trend in the past several years of a steep increase in non-Plan expenditure. We have been able to achieve it by enforcing the utmost economy and pruning in essential expenditures to the maximum extent possible.

27. The variations in non-Plan capital expenditure have been somewhat wider. There has been a net increase of Rs. 100 crores on account of technical credits to foreign countries under bilateral rupee trade agreements. These credits will be repaid when the imbalance in trade is corrected subsequently. The net outgo on account of fertilizer imports will be Rs. 190 crores more due partly to bunching of imports towards the end of the year, and partly to a rise in international prices.

28. As Hon'ble Members are aware, we have restored to the workers the minimum bonus of 8.33 per cent for the year 1976. A wage settlement was also reached with port and dock workers involving arrear payments from January, 1974. These have imposed an additional financial burden on public sector enterprises. This and certain other adverse factors have led to an increase of Rs. 113 crores in the budgetary support to public sector undertakings.

29. The expenditure on Defence continues to be the same as in the original Budget, viz. Rs. 2752 crores.

30. Revised Estimates show that Plan expenditure from the Budget on petroleum, fertilizers, steel and telecommunications is going to be substantially less than in the Budget. This was mainly due to slippages in delivery schedules of machinery and equipment and in civil construction. Also, a few public sector undertakings were able to generate more internal resources than anticipated earlier and therefore needed less budgetary support for financing their Plan outlay.

31. On the other hand, the total outlay on agriculture including rural development is expected to increase by Rs. 12 crores. Plan expenditure on health will also be higher by Rs. 13 crores, mainly on account of the intensification of the malaria eradication programme. New schemes and accelerated work on on-going schemes, specially those linked to steel and power plants, have led to an increase of Rs. 13 crores in the outlay on the coal sector.

32. Overall, the budgetary outlay on Central Plan schemes is expected to be Rs. 230 crores less than the original Budget provision of Rs. 3978 crores. I am not at all happy about the pace at which expenditure on Plan projects takes place. What is needed is a drastic change in organisation? It is proposed to devote much greater attention to this question in the coming months.

33. Central assistance to the States' Plans will be Rs. 2031 crores as against Rs. 1617 crores provided in the Budget. An additional sum of Rs. 414 crores was provided as a cover for the gap in States' resources for financing their Plans and as advance Plan assistance to the States affected by the recent unprecedented natural calamities.

34. When I presented the Budget last year I had estimated a budgetary deficit of Rs. 84 crores. This was after I had taken credit for a borrowing of Rs. 800 crores from the Reserve Bank of India on the assumption that foreign exchange reserves would be drawn down during the year. My anticipation of the country's ability to draw down the foreign exchange reserves has not materialised. Since I had made a clear commitment that I would use this credit from the Reserve Bank only if the reserves were drawn down, I do not propose to resort to this borrowing. The total budgetary deficit is now expected to be of the order of Rs. 975 crores. This may appear to be a sizeable sum but let me first clarify that of this amount, the sum of Rs. 414 crores is directly

accounted for by the additional assistance which I was compelled to make to the States on account of their deficits. Members will recollect that I had drawn attention to the improvident financial policies of the outgoing Governments in the States. In addition a number of States which suffered serious damage on account of cyclones and floods had also to be assisted. As a result there was substantial erosion of resources. It was my duty to assist the new Governments of the States so as to enable them to start on a reasonably clean slate. Having done so, I can reasonably expect them to manage their affairs hereafter in such a way that they do not need to have recourse to unauthorised overdrafts. I would like to state categorically that it will be my endeavour to put a stop to this unhealthy practice.

35. Another large sum of Rs. 190 crores is accounted for by importation of fertilizers. We have in fact by this process converted foreign exchange into a valuable fertilizer stock position and in this process we have not added to the money supply. Hon'ble Members will appreciate that despite what seemingly appears to be a major deficit, the Government's prudent policies of supply management and credit restraint have controlled any possible adverse effects and indeed we have ended the year with no inflation at all.

Budget Estimates for 1978-79

36. The Annual Plan for 1978-79 has been prepared pending the finalisation of the new National Plan. The Fifth Plan is being terminated at the end of the current financial year and the new Plan will start from 1st April, 1978. The Planning Commission is presently engaged in formulating the new strategy of development in keeping with the changed priorities. It will be finalised after the National Development Council deliberates upon it next month.

37. Hon'ble Members will appreciate that planning being a continuous process, at any point of time there is a large number of schemes and programmes under way which cannot be given up. Besides, many of these projects are in advanced stages of completion and therefore adequate provision is necessary if these are to yield timely results. These considerations have circumscribed our freedom in reordering Plan priorities for 1978-79. Nevertheless, I venture to say, the Annual Plan for 1978-79, as it has emerged, reflects the present Government's commitment to a new agriculture-oriented and employment-intensive strategy for development.

38. The total outlay on the Annual Plans of the Centre, States and Union territories for 1978-79 will be Rs. 11649 crores as against Rs. 9960 crores in 1977-78. This represents an increase of 17 per cent. Continuing schemes absorb as much as Rs. 10465 crores of this outlay. Out of the remainder, Rs. 150 crores have been allocated for starts on new power projects and Rs. 1034 crores for schemes under other sectors. As much as 80 per cent of the latter i.e. Rs. 828 crores, is accounted for by agricultural and other schemes subserving the development of rural areas.

39. The Central Budget for 1978-79 contains a provision of Rs. 7281 crores for the Central Plan and for assistance towards the Plans of States and Union territories. The corresponding figure for 1977-78 was Rs. 5790 crores.

40. A provision of Rs. 2761 crores has been made for Central assistance for States' Plans and for Union territories' Plans, the sub-Plans of the Hills and Tribal areas, North Eastern Council and assistance to the Rural Electrification Corporation. A provision of Rs. 4520 crores has been made in the Budget towards the Central Plan. Together with the internal and other resources of public sector undertakings, the Central Plan will be Rs. 5664 crores in 1978-79 as against Rs. 4939 crores in 1977-78. Inclusive of their own resources, the Plans of States and Union territories will add up to Rs. 5985 crores as compared to Rs. 5021 crores in 1977-78.

41. For the first time in many years, the States and Union territories' Plan together will be larger than the Central Plan. The step up in the outlay on States' Plans as a whole is 19 per cent while the Plans of the Union territories will go up by 27 per cent. The Central Plan, on the other hand, will increase by 15 per cent. This reflects a reordering of our Plan priorities in favour of agriculture, irrigation, power and rural development all of which figure prominently in States' Plans and in some measure a shift towards greater decentralisation in planning. Full provision has been made in each State's Plan for meeting the requirements of agriculture, the

on-going major and medium irrigation projects as well as power projects. Adequate provision has also been made for essential new schemes in these two sectors.

42. In keeping with our emphasis on agriculture and rural development, the Plan outlay for agriculture has been raised by Rs. 490 crores to Rs. 1754 crores for 1978-79. In particular the outlay on Command Area Development has been stepped up from Rs. 49 crores in 1977-78 to Rs. 82 crores in 1978-79 and that on Small Farmers' Development Agency in the Central Plan from Rs. 45 crores to Rs. 115 crores in 1978-79. The outlay on the drought prone area programme has been raised from Rs. 51 crores in 1977-78 to Rs. 76 crores for 1978-79. The desert development programme is being allocated Rs. 20 crores for 1978-79 as against only Rs. 6 crores in 1977-78.

43. In the new planning strategy, block development plans will be a major instrument for achieving full employment in rural areas in a time bound programme. The details of this programme are being worked out. In the meanwhile, I have made a token provision of Rs. 20 crores for this programme. This provision will be enlarged as the full details of the programme are known.

44. As part of the new strategy for rural development, it is proposed to launch a massive programme of dairy development—Operation Flood II—which will raise the nutritional standards of the people, generate employment for about 4 million people in the first phase and augment the incomes in rural areas through a viable subsidiary occupation. The project which is estimated to cost nearly Rs. 500 crores is being processed for implementation but meanwhile action on certain essential pre-programme elements has already been authorised so that the main work on the programme may start in time.

45. Having regard to the extensive coastline of our country and the large numbers of people engaged in fisheries, the outlay on fisheries in the Central Plan is being raised from Rs. 33 crores in 1977-78 to Rs. 61 crores in 1978-79. This enhanced outlay will, apart from strengthening basic infrastructural facilities, enable us to enlarge employment and augment the incomes of fishermen.

46. In my last Budget speech, I had indicated that as part of a comprehensive programme of rural infrastructure development it was necessary to accelerate the construction of all-weather approach roads and the provision of drinking water facilities in problem villages. In 1978-79, the outlay on rural roads in the States' Plans has been stepped up to Rs. 115 crores as against the current year's outlay of Rs. 85 crores. The provision for rural water supply in the States' Plans in 1978-79 will be Rs. 105 crores as against Rs. 70 crores in the current year. This will be supplemented by a special provision in the Central Plan to the extent of Rs. 60 crores. The promise made last year that the allocations for rural water supply and rural roads will be enhanced has thus been redeemed. I will go further and extend an assurance to the States that if these programmes are implemented effectively I shall be prepared to consider increasing these allocations.

47. I have already emphasised the need to improve the opportunities for gainful employment in rural areas through the development of rural and small scale industries. The total allocation for these in 1978-79 will be Rs. 219 crores against Rs. 145 crores in 1977-78.

48. The programmes for welfare of the Scheduled Castes and other backward classes will receive a special impetus with a step up in the outlay from Rs. 86 crores in 1977-78 to Rs. 125 crores in 1978-79. The outlays in the States' Plans for tribal development will be increased from Rs. 258 crores in 1977-78 to Rs. 343 crores in 1978-79. In addition, the special Central assistance for tribal sub-Plans will be stepped up from Rs. 55 crores in 1977-78 to Rs. 70 crores in 1978-79.

49. The creation of an additional irrigation potential of 17 million hectares during the next five years is an ambitious programme which will call for a large increase in investment and a restructuring, strengthening and streamlining of the organisational set-up for planning, execution and monitoring. The outlay on major and medium irrigation projects for 1978-79 will be Rs. 1166 crores as against Rs. 1032 crores in 1977-78. The Plan outlay for minor

irrigation will be Rs. 235 crores in 1978-79 as against Rs. 206 crores in 1977-78. It will be supplemented to a large extent by loans from the Agricultural Refinance and Development Corporation. It is expected that an additional irrigation potential of 3 million hectares will be created during 1978-79 as against 2.23 million hectares in 1977-78.

50. Inadequate allocations in the past for power and the leisurely pace of execution of electricity projects have led to a chronic shortage of this basic infrastructure facility. Both these need to be corrected if recurrent power shortages are not to hold up our progress. Therefore the Plan for 1978-79 envisages a massive addition to generating capacity and the development of the transmission and distribution system. Works on schemes with a total capacity of about 30000 MW would be in different stages of execution in the coming year. Of this about 3500 MW will be commissioned in 1978-79 as against about 2000 MW expected in the current year and the total generating capacity in the country will then be raised to 29000 MW.

51. In the Central sector, provision is being made for fresh starts on a number of projects such as the Korba super thermal project, the Ramagundam super thermal project, the power station including the second mine cut at Neyveli, the Badarpur thermal station stage III, the Bokaro thermal station of DVC, and the pumped storage plant of Panchet Hill. Provision has also been made for taking up new 400 KV transmission lines in the Central sector associated with super thermal stations and in the States. Work on load despatch stations is also being accelerated. This should give the House an idea of the programme of power generation which we are going to undertake.

52. A sum of Rs. 244 crores has been provided in the Central Plan for power development. The outlays in States' and Union territories' Plans, which account for bulk of the provision for power, add up to Rs. 1953 crores. The provision in 1978-79 for the power sector would be Rs. 2217 crores compared to Rs. 1925 crores in the current year. In view of the importance of rural electrification the provision for it has been raised to Rs. 297 crores as compared to Rs. 195 crores in the current year. We shall ensure that these projects are implemented quickly and efficiently so that the economy derives full benefit from such a large volume of investment.

53. A provision of Rs. 630 crores is being made for the oil sector in 1978-79 because there can be no slackening of our efforts towards self-sufficiency in crude oil. This is yet another step forward in the nation's march towards self-reliance.

54. A Budget provision of Rs. 563 crores is being made for steel in 1978-79 as against Rs. 511 crores during 1977-78. The requirements of Bhilai and Bokaro expansion programmes, the cold rolled grain oriented plant at Rourkela and the Salem steel plant have been met. The outlay on Kudremukh project is being stepped up from Rs. 142 crores in 1977-78 to Rs. 213 crores next year, in order to be able to meet the deadline set for the completion of the project.

55. An impression has been sought to be created that this Government is giving less emphasis to family planning. Such an impression is totally unwarranted. Our commitment to a vigorous and nation-wide programme of family planning is firm and clear. A provision of Rs. 393 crores is being made in 1978-79 for health and family welfare as against only Rs. 284 crores in 1977-78. It is now felt that instead of concentrating only on the narrow aspects of family planning a broader concept of family welfare will lead to a better acceptance of family planning practices. Funds have also been provided on an adequate scale both in the Central and States' Plans for expansion of health cover for rural areas including the Scheme for community health workers.

56. This Government fully recognises that science and technology have a valuable contribution to make in the modernisation of our economy and in the growth of agriculture and industry. Hon'ble Members will be glad to know that the outlay on science and technology has been increased from Rs. 1977 crores in 1977-78 to Rs. 220 crores for 1978-79, i.e., an increase of 23 per cent. Similarly the provision for the Indian Council for Agricultural Research

has been increased from Rs. 37 crores in 1977-78 to Rs. 51 crores for 1978-79. The Indian Satellite Project (INSAT-I) for which a provision of Rs. 23 crores has been made for 1978-79 also needs special mention. This project is unique in that it combines a package of facilities covering telecommunications, meteorology and television.

57. Non-Plan revenue expenditure, other than Defence, is estimated at Rs. 5908 crores showing an increase of Rs. 354 crores over the Revised Estimates for the current year. Interest payments and grants to States together account for an increase of Rs. 384 crores. If we exclude these two items, the other non-Plan revenue expenditure will be less than the Revised Estimates for the current year. This has been made possible by a rigorous scrutiny of non-Plan expenditure, pruning it with a view to achieving the utmost economy. The various subsidy payments have also been reviewed in the light of their continued relevance in the present economic situation and the provisions therefor have been suitably reduced. Non-Plan budgetary support to public sector enterprises will also be Rs. 127 crores less than in the current year.

58. Defence expenditure next year will be Rs. 2945 crores, as against Rs. 2752 crores in the current year.

59. Gross tax revenue for 1978-79, at the existing rates of taxation, is expected to amount to Rs. 9636 crores showing an increase of Rs. 730 crores over the Revised Estimates for the current year. Income tax and corporation tax receipt are expected to go up by Rs. 115 crores and Rs. 145 crores respectively. Union excise duties are estimated to yield Rs. 374 crores more. The yield from customs revenue will also be more by Rs. 70 crores. States' share of taxes and duties, at Rs. 1929 crores, will be higher by Rs. 130 crores.

60. Market loans will yield Rs. 1650 crores as compared to Rs. 1183 crores in the current year. Net external assistance, after providing for repayments and interest payments, is estimated at Rs. 1138 crores, including disbursements against new credits.

61. Taking other receipts into account, total receipts in 1978-79 are estimated at Rs. 17021 crores. Total expenditure for the coming year will be Rs. 18417 crores. The overall budgetary gap at the existing rates of taxation will thus be Rs. 1396 crores. Hon'ble Members will recollect that Government announced yesterday their decision to sanction with effect from 1st January, 1978 another instalment of dearness allowance to Central Government employees. Government's new policy in regard to sugar industry was also announced yesterday. These two decisions may cast an additional burden of the order of Rs. 80 crores on the Central exchequer next year. Understandably I have not taken this into account in my Budget proposals. It is, however, my hope that this additional burden will be substantially accommodated within the Budget Estimates by economy measures which are being progressively implemented.

बजट 1978-79

बित्त मंत्री का भाषण

28 फरवरी, 1978

भाग 'ख'

62. जाहिर है कि यह 1396 करोड़ रुपए का घाटा बहुत अधिक है और इसे पूरा करने के लिए अर्थोपाय ढूँढ़ने का कठिन और चुनौतीपूर्ण भार मेरे कंधों पर है। मैं देश की अर्थव्यवस्था की बहुत-सी अनुकूल बातों का उल्लेख कर चुका हूँ जो हमें इतने बड़े किन्तु औचित्यपूर्ण घाटे के होते हुए भी, मुद्रास्फीति की स्थिति को पैदा किए बिना, अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक तरह से संचालित करने के लिए आवश्यक शक्ति और अवसर प्रदान करती हैं। किन्तु समझदारी का तकाजा है कि घाटे को, चाहे वह कितना ही औचित्यपूर्ण क्यों न हो, यथासम्भव कम से कम स्तर पर रखा जाना चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि जहाँ तक सम्भव हो ज्यादा से ज्यादा अतिरिक्त साधन जुटाए जाएं। मुझे विश्वास

है कि राष्ट्र इतने बड़े आकार की राष्ट्रीय आयोजना को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सहर्ष योगदान देगा जिसके सहारे हम अपने गन्तव्य पर तीव्रतर गति से पहुँच सकेंगे।

63. साधन जुटाने के अपने प्रस्तावों को तैयार करते समय, मैंने कराधान (टैक्सेशन) नीति के उन हितकारी सिद्धान्तों को ध्यान में रखा है, जो कि जनता पार्टी के, नवम्बर, 1977 में जारी किए गए आर्थिक नीति संकल्प में निर्धारित किए गए हैं। इन सिद्धान्तों को यहाँ दोहरा देना उचित होगा।

"हमारी मान्यता है कि सरकार को अपनी कराधान नीति निर्धारित करने समय पांच बातें ध्यान में रखनी चाहिए, अर्थात् :—

- (1) सरकारी निवेश (इन्वेस्टमेंट) व्यय को बढ़ाने के लिए सरकारी धाया बढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए भविष्य में किए जाने वाले निवेश के लिए आवश्यक ऊँचे करों का बोझ देश की जनता को उठाना ही पड़ेगा।
- (2) साथ ही कराधान नीति का उद्देश्य समन्यायपूर्ण व्यापक वितरण की व्यवस्था होना चाहिए और इसमें भ्रष्टाचारी कर सकने की क्षमता को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- (3) कर ऐसे होने चाहिए जिनको वसूल करना आसान हो और करदाता आसानी से यह जान सके कि उसे कितनी रकम भ्रष्टा करनी है। कर प्रशासन को सरल तथा युक्तिसंगत बनाने की अविलम्ब आवश्यकता है।
- (4) करों में अन्तर्निहित वृद्धिशीलता और कमी को पूरा करने की सहज क्षमता होनी चाहिए।
- (5) कराधान नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना होना चाहिए और उससे उत्पादन और बचतों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।"

64. मुझे इस सम्बन्ध में समाज के सभी वर्गों और देश के सभी भागों से परामर्श प्राप्त करने का सौभाग्य भी मिला है। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में मुझे दो महत्वपूर्ण रिपोर्टें अर्थात् प्रत्यक्ष करों (डाइरेक्ट टैक्सेज) के सम्बन्ध में चौकशी समिति की अन्तिम रिपोर्ट और अप्रत्यक्ष करों के बारे में ज्ञा समिति की अन्तिम रिपोर्टें मिली हैं। इन रिपोर्टों में बहुत से उपयोगी सुझाव दिए गए हैं और मैंने उन पर सम्मानपूर्वक विचार किया है।

65. अपने कराधान (टैक्सेशन) प्रस्तावों का निरूपण करने से पहले मैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी घोषणाएं करना चाहता हूँ, जो इस बजट से सम्बन्ध रखती हैं।

66. ऊँचे मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का विमुद्रीकरण (डिमोनेटाइजेशन) किए जाने का उद्देश्य मुख्य रूप से अवैध लेन-देनों पर अंकुश लगाना था। सरकार द्वारा किया गया यह उपाय उन उपायों की शृंखला में से एक है जिन्हें सरकार समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध उपयोग में लाने के लिए दृढ़प्रतिष्ठ है। सीमा-शुल्क अधिकारियों की कड़ी निगरानी और तस्करी से आए सोने की बरामदगी और जख्ती के बावजूद भी, दुःख और दुर्भाग्य की बात यह है कि सोने का तस्करी व्यापार किसी हद तक होता ही रहा है। भारत में सोने की कीमतों और अन्तर्राष्ट्रीय सोने की कीमतों के बीच जो भारी अन्तर है वही तस्करी के लिए एक बड़ा प्रलोभन है। सोने का तस्करी व्यापार (स्मगलिंग) न केवल गैर-कानूनी है बल्कि इसकी वजह से काले धन का कारबार कायम रहा है और विदेशी मुद्रा का अवैध धन्धा (रैकेटियरिंग) पनपा है। इसलिए सोने के तस्करी व्यापार की इस बुराई को दूर करने के लिए यह जरूरी है कि हम इस व्यापार की रोकथाम करने के उपायों के अलावा कुछ आर्थिक उपायों को अपनाने पर भी विचार करें। हमने इस प्रश्न पर बड़े ध्यान से विचार किया है और सरकारी भण्डारों से सोने की बिक्री शुरू करने का फैसला किया है।

इस योजना का ब्योरा तयार किया जा रहा है और भीघ्र ही उसकी घोषणा कर दी जाएगी।

67. विदेशों में भारतीय सोने के आभूषणों की बहुत ज्यादा मांग है। इससे न केवल हम बहुत अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकेंगे, बल्कि भारतीय जीवहरियों की अद्वितीय कारीगरी को भी लाभोपाजक (गेनफुल) उपयोग में ला सकेंगे। अब तक सोने की ऊँची स्थानीय कीमतों, सोने के आभूषणों के निर्यात पर लगी पाबन्दियों और बन्धपत्र देने (बॉन्डिंग) की पेचीदा और बाधक प्रक्रियाओं के कारण सोने के आभूषणों के निर्यात में भारी रुकावटें आती रही हैं। इसलिए सरकार ने सोने के आभूषणों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए एक सरल योजना लागू करने का फैसला किया है। इस तरह के स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के लिए या तो सोने का आयात करने की अनुमति देकर अथवा सरकारी सोने के भण्डार से अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर सोने को बेचकर सुविधा दी जाएगी। इस योजना के ब्योरे की भीघ्र ही घोषणा की जाएगी।

68. सम्मानित सदस्यों को स्मरण होगा कि जनता पार्टी के घोषणापत्र (मैनिफेस्टो) में कहा गया था कि सरकार बिक्री-कर और चुंगी (ऑक्ज्ज) हटाने के प्रश्न पर भली भाँति विचार करेगी। इस बांछनीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा वित्त मंत्रियों से कई बार बातचीत की है। बिक्री-कर से कुल मिलाकर 2,500 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। बिक्री-कर ही राज्यों के राजस्व का मुख्य साधन है। राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने आमतौर पर बिक्री-कर को हटा देने के मामले में कोई उत्साह नहीं दिखाया है। राज्यों के इस रवैये को ध्यान में रखते हुए और यह देखते हुए कि बिक्री-कर हटा देने के मामले में राजी करने के लिए लगातार आग्रह करते रहने और धैर्य से काम लेने की जरूरत है, निरवय ही इसे कोई ऐसा काम नहीं समझ लिया जाना चाहिए कि जिसे निकट भविष्य में सम्पन्न किया जा सकता है।

69. किन्तु चुंगी की स्थिति दूसरी तरह की है। चुंगी से 250 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। इस अनचाहे महसूल को हटाने के लिए जिससे व्यापारियों को तथा परिवहन उद्योग को भारी अनुसुधिया होती है बड़े लम्बे अरसे से मांग की जा रही है। जिन सभी समितियों ने इस विषय का अध्ययन किया है एकमत से इसे हटा देने की सिफारिश की है। अध्ययनों से यह भी जाहिर हुआ है कि चुंगी वसूली के काम पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। इस बात पर दो मत नहीं हो सकते कि चुंगी को हटा दिए जाने की कार्रवाई का व्यापक रूप से स्वागत होगा क्योंकि इसको समाप्त कर देने से देश की परिवहन (ट्रान्सपोर्ट) व्यवस्था के सुधवस्थित और स्वस्थ विकास में सहायता मिलेगी और गाल-भाड़े की लागत भी काफी कम हो जाएगी। इसलिए मैं राज्य सरकारों से यह अनुरोध करने का प्रस्ताव करना चाहता हूँ कि वे चुंगी को समाप्त करने के लिए मुनासिब कानून लागू करें। इस समय चुंगी की आमदनी स्थानीय प्राधिकरणों (लोकल ऑथोरिटीज) को प्राप्त होती है। इसलिए स्वाभाविक है कि स्थानीय प्राधिकरण चुंगी के राजस्व की हानि के लिए राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति (रि-इम्बर्समेन्ट) की मांग करेंगे और राज्य सरकारें निस्सन्देह केन्द्र से तत्सम्बन्धी मुआबजा देने की मांग करेंगी। इसका सन्तोषजनक समाधान ढूँढने के लिए हम राज्य सरकारों से बातचीत करेंगे।

70. अब मैं कुछ शब्द अपने साथी संचार मंत्री की ओर से कहूँगा। पिछले कुछ एक वर्षों में कर्मचारियों के वेतन-अर्तां प्राथि में की गई वृद्धि के कारण डाक-तार विभाग की डाक शाखा के व्यय में जो कि बहुत अधिक श्रम-प्रधान (लेबर इन्टेंसिव) है बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। किन्तु व्यय के बढ़ने के साथ-साथ राजस्व में उतनी वृद्धि नहीं हुई है और विभिन्न डाक सेवाओं का खर्चा अर्जित राजस्व के मुकाबले कहीं ज्यादा हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप डाक-शाखा घाटा उठाती चली आ रही है और अनुमान है कि चालू वर्ष में यह घाटा लगभग 23 करोड़ रुपए का है। इसलिए यद्यपि अधिकतर डाक सेवाओं की शुल्क

दरों में वृद्धि करने का औचित्य है तथापि केवल उन्हीं डाक सेवाओं के शुल्क में वृद्धि करने का प्रस्ताव है जिनसे जनसाधारण पर खास तौर से ग्रासीण क्षेत्रों में कोई असर नहीं पड़ेगा। बजट-वर्षों के साथ एक गणन भी दिया जा रहा है जिसमें डाक शुल्क दरों (पी० एण्ड टी० टैरिफ) में किए गए परिवर्तनों का ब्योरा दिया गया है।

71. अनुमान है कि शुल्क दरों के इन परिवर्तनों से जिन्हें वित्त विधेयक अधिनियमित हो जाने के बाद सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख से लागू किया जाएगा, प्रतिवर्ष 13.73 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। अनुमान है कि 1978-79 में 11.44 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। शुल्क दरों के परिवर्तनों के परिणामस्वरूप होने वाली आमदनी को डाक-तार के आन्तरिक साधनों का अनुमान लगाते समय हिसाब में शामिल कर लिया गया है।

72. अब मैं प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित अपने प्रस्तावों के बारे में कहूँगा।

73. मैंने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि निवेश में की जाने वाली सारवान (सबस्टैणियल) वृद्धि को सहाय्य देने के लिए यह जरूरी है कि बचतें जुटाने के लिए और ज्यादा कोशिश की जाए। इसलिए प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र से सम्बन्धित मेरे प्रस्तावों का उद्देश्य यह है कि बचतें और ज्यादा बढ़ें, कारबार तथा व्यवसाय के क्षेत्र में बेशुमार फिजूल-खर्ची बन्द हो और विकास तथा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए धन-राशियों का उपयोग हो। यांछित दिशाओं में और ज्यादा पूंजी के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ नूतने हुए क्षेत्रों में कर सम्बन्धी राहत देने की व्यवस्था भी मैंने की है।

74. बचत के रूप में अतिरिक्त साधन जुटाने के उद्देश्य से मैं आयकर-दाताओं के मामले में अनिवार्य जमा (कम्पल्सरी डिपॉजिट) की दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूँ। ऐसे करदाताओं को जिनकी वर्तमान आय 15000 रुपए तक है, आय भी अनिवार्य रूप से एक जमा नहीं करानी होगी परन्तु 15000 रुपए से ऊपर और 25000 रुपए तक की आय के मामले में इस दर को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 4½ प्रतिशत कर दिया जाएगा। 25001 रुपए से 70000 रुपए के आय-खण्ड में इस समय 10 प्रतिशत की दर से अनिवार्य रकम (कम्पल्सरी डिपॉजिट) जमा करानी पड़ती है। मैं इस आय-खण्ड को दो भागों में विभक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अनुसार 25001 रुपए से 35000 रुपए के आय-खण्ड के लिए अनिवार्य जमा की दर 11 प्रतिशत होगी और 35001 रुपए से 70000 रुपए तक के आय-खण्ड के लिए यह दर 12½ प्रतिशत होगी। 70000 रुपए से ऊपर के आय-खण्ड के लिए इस दर को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इस उपाय से 1978-79 में लगभग 25 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी।

75. मैं जीवन बीमा भविष्य निधि अंशदानों और बचत के अन्य अनुभांजित रूपों के माध्यम से की जाने वाली दीर्घाधिक बचत से संबंधित रियायत को भी उदार बनाना चाहता हूँ। इस समय कराधान-योग्य आय (टेक्सबल इन्कम) का निर्धारण करने के लिए रियायत की पात्रता वाले बचतों के पहले 4000 रुपए के 100 प्रतिशत अंश की, अगले 6000 रुपए के 50 प्रतिशत अंश की तथा शेष राशि के 40 प्रतिशत अंश की कटौती की जाती है। किन्तु मैं रियायत की पात्रता वाली बचतों के पहले 5000 रुपए के 100 प्रतिशत के बराबर की कटौती किये जाने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे अगले 5000 रुपए के संबंध में 50 प्रतिशत की वर्तमान दर पर और इसी प्रकार शेष राशि के सम्बन्ध में 40 प्रतिशत की वर्तमान दर पर कटौती की जाती रहेगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत कटौती की पात्रता प्राप्त करने वाली बचतों की मौद्रिक सीमा को भी 20000 रुपए से बढ़ाकर 30000 रुपए किया जा रहा है एक पूरे वर्ष में इन उपायों से 10 करोड़ रुपए और 1978-79 में 7 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

76. पूंजी लगाने वाले लोग स्वभावतः ऐसे निवेश को पसंद करेंगे जिससे उन्हें जोखिम के बिना आमदनी हो और इस तरह की आमद

उन्हें या तो बैंकों में भोयादी जमा से या ऐसी सुप्रतिष्ठित कम्पनियों के शेयरों में रकम लगाने से हासिल होती है जो आज तक अच्छा लाभान्वित प्रदा करती रही हैं। इसका परिणाम यह होता है कि नई कम्पनियों को पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता। अतः इस प्रकार की नई कंपनियों में पूंजी-निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैं कराधान योग्य आय का हिसाब लगाने के मामले में नई औद्योगिक कम्पनियों की सामान्य गेयर पूंजी में लगाने पर रकम के 50 प्रतिशत तक कटौती की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। एक वर्ष में इस प्रकार की कटौती की पावता प्राप्त करने वाले निवेश की अधिकतम सीमा 10000 रुपए होगी। इस उपाय से एक पूरे वर्ष में 5 करोड़ रुपए की और 1978-79 में 3.5 करोड़ रुपए की हासिल होगी। मैं तो खुशी से, इससे भी ज्यादा हासिल बढ़ाकर करने के लिए तैयार हूँ बशर्ते कि इससे पूंजी निवेश को बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलता हो।

77. पिछले वर्ष मैंने पूंजी अभिलाषाओं (कैपिटल गेन) को उन मामलों में छूट देने की व्यवस्था की थी, जिनमें किसी परिसंपत्ति के अन्तरण से प्राप्त होने वाली बिक्री की रकम को छः महीने के अन्दर-अन्दर भारतीय यूनिट ट्रस्ट के गुणितों, भारतीय कम्पनियों के शेयरों, बैंकों की जमा राशियों या अन्य विनिर्दिष्ट परिसंपत्तियों (स्पेसिफाइड एसेट्स) में फिर से लगा दिया गया हो। इस उद्देश्य को सामने रखते हुए कि इस रियायत से निवेश योग्य धनराशियाँ नए उपकरणों में लगाई जाएँ, मैं तात्कालिक प्रभाव से, यह व्यवस्था करता हूँ कि भारतीय कम्पनियों के शेयरों में किये गये निवेश को, पूंजी अभिलाषा कर से छूट दिये जाने के प्रयोजन से केवल उसी स्थिति में हिसाब में लिया जाएगा जबकि ऐसा निवेश नई औद्योगिक कम्पनियों के सामान्य शेयरों में किया गया होगा।

78. बैंक अपने यहां जमा की गई मियादी रकमों (फिक्स्ड डिपॉजिट) की जमानत पर काफी ऋण दे देते हैं। इस तरह से वे करदाता, जो इस तरह की रकमों जमा कराकर पूंजी अभिलाषा कर से छूट प्राप्त कर लेते हैं, तदनुकूल त्याग किए बिना ही, अनुचित रूप से कर सम्बन्धी भारी फायदा उठा जाते हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज के बाद से बैंकों के पास जमा भोयादी रकमों का इस छूट के प्रयोजनों के लिए निवेश का पात्रता प्राप्त तरीका नहीं माना जाएगा।

79. नए बनाए गए मकान के वार्षिक किराया मूल्य में से, प्रत्येक रिहायशी इकाई के सम्बन्ध में, पांच वर्ष की अवधि तक, कर के प्रयोजनों के लिए 1200 रुपए तक की रकम घटा दी जाती है। मकान के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, खास तौर पर कम आयदनी और वरमियानी आयदनी वाले वर्गों के लोगों को मकान बनाने के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, मैं इस रकम की सीमा को 1200 रुपए से बढ़ाकर 2400 रुपए कर देने का प्रस्ताव करता हूँ।

80. नियोजकों (एम्प्लॉयर्स) के द्वारा उनके कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए बनाई गई नई इमारतों की लागत पर इस समय 20 प्रतिशत की दर से प्रारंभिक मूल्यह्रास छूट दी जाती है। कर्मचारियों के लिए इमारतों के निर्माण को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रारंभिक मूल्यह्रास छूट (डेप्रिषियेशन एलाउंस) की दर को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाए।

81. भारत से बाहर नियोजित भारतीय नागरिकों के विदेशी पारि-श्रमिक पर भारतीय आयकर उस दशा में लगता है जबकि ऐसे व्यक्ति भारत में एक विनिर्दिष्ट अवधि से ज्यादा अर्द्ध तक ठहरे। चूंकि इससे उन लोगों को परिहार्य कठिनाई का सामना करना पड़ता है और इसकी वजह से वे अपने ही देश में अवकाश की उचित अवधि बिताते के लिए निरु-त्साहित होते हैं, इसलिए मैं इस बात की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ कि भारत से बाहर नियोजित भारतीय नागरिक देश में एक वर्ष में 89 दिन तक का अवकाश इस तरह की कर सम्बन्धी वेतनदारी से मुक्त रह कर बिता सकेंगे।

82. इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए कि बुँडूदौड़ में जीती हुई रकमों (हास रेस विनिंग्स) पर भी प्रभावपूर्ण बंग से कर

लगाया जाए, मैं यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ कि 2500 रु० से अधिक रकम की जीत होने पर 34.5 प्रतिशत की दर से, खीन पर ही कर की कटौती कर ली जाए। इस उपाय से एक पूरे वर्ष में 4 करोड़ रुपए और 1978-79 में 3.5 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी।

83. विज्ञापन, प्रचार और बिक्री संवर्द्धन के कार्यों पर प्रायः बहुत ज्यादा खर्चा किया जाता है जो सामाजिक दृष्टिकोण से फिजूल होता है। इस प्रकार के खर्च पर पाबंदी लगाने के लिए, ताकि राजस्व की हानि न हो, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कराधान योग्य लाभ का हिसाब लगाने में इस प्रकार के खर्च के अंश के लिए कोई छूट न दी जाए। जिस मामले में, विज्ञापन, प्रचार तथा बिक्री संवर्द्धन के कार्यों पर भारत में किया गया कुल व्यय, कारखाना या व्यवसाय की कुल टर्न ओवर या उसकी सकल प्राप्तियों के $\frac{1}{2}$ प्रतिशत से अधिक न हो, उस मामले में, कराधान योग्य लाभ का हिसाब लगाने के लिए इस प्रकार के व्यय का 10 प्रतिशत भाग छूट के प्रयोजन के लिए हिसाब में शामिल नहीं किया जाएगा। जिस मामले में इस प्रकार का व्यय कुल कारखाने की रकम या सकल प्राप्तियों के $\frac{1}{2}$ प्रतिशत से ज्यादा हो किन्तु $\frac{1}{2}$ प्रतिशत से ज्यादा न हो, उनमें इस प्रकार के व्यय का $\frac{1}{2}$ प्रतिशत भाग छूट के प्रयोजन के लिए हिसाब में शामिल नहीं किया जाएगा और जिन मामलों में, इस प्रकार का व्यय टर्न ओवर या सकल प्राप्तियों के $\frac{1}{2}$ प्रतिशत से ज्यादा हो उसमें इस प्रकार के व्यय का 15 प्रतिशत भाग का हिसाब में शामिल नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था उन मामलों में लागू नहीं होगी, जिनमें विज्ञापन, प्रचार तथा बिक्री संवर्द्धन कार्यों पर किया गया कुल व्यय, एक वर्ष में 20000 रुपए से अधिक न हो। इस व्यवस्था से, नए स्थापित प्रतिष्ठानों को तीन वर्ष तक की प्रारंभिक अवधि के लिए छूट दी जाएगी। एक पूरे वर्ष में इस उपाय से 31 करोड़ रुपए की और 1978-79 में 25 करोड़ रुपए की आयदनी होगी।

84. कराधान योग्य लाभों का हिसाब लगाने के लिए भारतीय कम्पनियों तथा कम्पनियों से मिश्र निवासी करदाताओं के द्वारा नियत बाजार का विकास करने के लिए किए गए खर्च के सम्बन्ध में इस समय भारत कटौती की जा सकती है। बहु-जन-वारित कम्पनियों (वाइडली-हेल्ड कम्पनीज) के मामले में यह भारत कटौती वास्तविक व्यय के 150 प्रतिशत की दर से और अन्य करदाताओं के मामले में यह कटौती 133.3 प्रतिशत की दर से की जा सकती है। यद्यपि नियत बाजार का विकास करने के लिए किये गये व्यय की पूरी कटौती पूर्णरूप से औचित्यपूर्ण है, और विज्ञापन, प्रचार तथा बिक्री संवर्द्धन पर किये जाने वाले व्यय अस्वीकृत किए जाने की प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार के व्यय के किसी भी भाग को अस्वीकृत नहीं किया जाएगा, तथापि अब मुझे भारत कटौती की स्वीकृति के जरिये इस प्रकार के व्यय के लिए आर्थिक सहायता दिये जाने का कोई पर्याप्त औचित्य नजर नहीं आता। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1978 के बाद किए गए इस प्रकार के व्यय के सम्बन्ध में भारत कटौती जारी न रखी जाए। इस उपाय से, एक पूरे वर्ष में, 10 करोड़ रुपए और 1978-79 में 8 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी।

85. ऐसे करदाता के मामले में, जिस पर पहले आयकर लगाया गया है, अग्रिम कर तभी देय होता है जब आयकर अधिकारी इस सम्बन्ध में नोटिस जारी कर देता है। इसलिए, इस तरह के करदाता के मामले में यदि अग्रिम कर के लिए नोटिस जारी नहीं किया जाता तो वह कोई अग्रिम कर देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। दूसरी ओर, जिन करदाताओं के मामले में आयकर का निर्धारण नहीं किया गया है, उन्हें अपनी वर्तमान अनुमानित आय के आधार पर अपने आप अग्रिम कर देना होता है। मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में वर्तमान कानूनी स्थिति स्पष्टतः असन्तोषजनक है। अतः मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को स्वेच्छा से अग्रिम कर देना होगा जिसकी वर्तमान आय विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक होगी।

86. श्री सी० सी० चौकशी की अध्यक्षता में जो प्रत्यक्ष कर विधि समिति बनाई गई थी, उसने पिछले विसम्बर महीने में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट पेश कर दी थी। इस रिपोर्ट में, कर सम्बन्धी कानूनों को सरल

तथा युक्तिसंगत बनाने, कर निर्धारण करने की कार्य प्रणाली को सुचारु बनाने, मुकदमों/बाजी का क्षेत्र कम करने और अपीलों तथा निर्देशों (रेफ़ेंस) को निपटाने की गति तेज करने के लिए कई मूल्यवान सुझाव दिए गए हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर प्रशासन विषयक अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि कर सम्बन्धी कानूनों में वार्षिक वित्त विधेयक के जरिये संशोधन करने की जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इस विधेयक को एक निश्चित तारीख से पहले पास करना पड़ता है, परन्तु उक्त संशोधन अवगण से विधेयक लाकर किए जाने चाहिए, जिन पर व्यापक रूप से विचार किया जा सकता है। इस सिफारिश के अनुसरण में, मैं चौथी समिति की उन मुख्य सिफारिशों को लागू करने के लिए, जो सरकार को मान्य हैं, यथाशीघ्र अवगण से एक कानून बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। इस बीच, समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर कुछ संशोधनों, जैसे धुड़-दोड़ में जीती गई रकमों के सम्बन्ध में स्रोत पर कर की कटौती तथा स्वेच्छा से अधिम कर की अदायगी से सम्बन्धित संशोधनों को, वित्त विधेयक के जरिये पेश किया जा रहा है, जिन्हें आसानी से कर सम्बन्धी कानून में शामिल किया जा सकता है।

87. सम्पदा-शुल्क (एस्टेट ड्यूटी) से छूट देने की सीमा आज से कई साल पहले 1958 में 50,000 रुपये निर्धारित की गई थी। चूंकि छूट की यह सीमा काफी कम है इसलिए मैं, इसे बढ़ा कर एक लाख रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ। चूंकि इस मामले में हम राज्यों के विधान-मण्डलों की सहमति से ही आवश्यक विधेयक ला सकते हैं इसलिए इस प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए एक विधेयक तथा सम्पदा शुल्क से सम्बन्धित कुछ अन्य प्रस्ताव इस वर्ष, बाद में पेश किए जाएंगे।

88. मैंने जिन विभिन्न उपायों का उल्लेख किया है उनसे पूरे वर्ष में कुल मिलाकर 30 करोड़ रुपये और 1978-79 के दौरान 25.5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 1978-79 में अनिवार्य जमा की रकमों के रूप में लगभग 25 करोड़ रुपये के अतिरिक्त साधन प्राप्त होंगे।

89. अब मैं अपने अप्रत्यक्ष कर (इन्डायरेक्ट टैक्स) प्रस्तावों की ओर आता हूँ। हमारी राष्ट्रीय बुनियादी समस्या, जो वास्तव में सभी विकासशील देशों के सामने है, यह है कि प्रत्यक्ष करों का आधार बिल्कुल संकुचित है और इसलिए हमारे राष्ट्रीय विकास के लिए जितनी भारी मात्रा में धनराशि की जरूरत है उसनी धनराशि हमारे विकास की वर्तमान अवस्था में प्रत्यक्ष करों से नहीं जुटाई जा सकती। प्रत्यक्ष करों से संबंधित अपने प्रस्ताव तैयार करते समय मैंने यह बात ध्यान में रखी है कि लघु उद्योग को संरक्षण देना तथा गरीब और मध्य आय वर्ग के लोगों की कठिनाई को संभव सीमा तक कम करना जरूरी है।

90. सम्मानित सदस्यों को मालूम है कि सरकार ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के वर्तमान ढाँचे की समीक्षा करने के लिए श्री लक्ष्मीकान्त झा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने अब अपनी अन्तिम रिपोर्ट दे दी है। समिति ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये वे ये हैं:— केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्कों की प्रणाली का ढाँचा फिर से तैयार करना, लघु उद्योग क्षेत्र को सहायता देने के लिए कदम उठाना, शुल्क दरों में सामान्य रूप से ऐसा परिवर्तन करना कि जैसे-जैसे आय बढ़े वैसे-वैसे दर में भी वृद्धि होती जाए और संयोजित मुख्य कर (वैल्यू ऐडेड टैक्स) लागू करने की बांछनीयता पर विचार करना ताकि कच्चे माल और तैयार वस्तुओं के संघटकों को करों के बहुस्तरीय प्रभाव से अवगणित जा सके। समिति ने राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष करों के बारे में भी सुझाव दिए हैं। सरकार इन सभी सुझावों पर यथोचित सावधानी के साथ विचार करती रही है। वास्तव में, मैंने पिछले बजट में, समिति के कुछ सुझावों को, जो हमें उसकी अन्तरिम रिपोर्ट में उपलब्ध थे, स्वीकार कर लिया था और उन्हें क्रियान्वित भी कर दिया था। आज मैं जो प्रस्ताव रख रहा हूँ उनमें वे कुछ सुझाव शामिल किए गए हैं जो उक्त समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में दिये थे। समिति के अन्य सुझावों के सम्बन्ध में, जो कर प्रणाली के ढाँचे

में भारी परिवर्तन किये जाने के बारे में हैं, आगे और अध्ययन करने की आवश्यकता होगी।

91. आयोजना परिषद में सर्वोच्च प्राथमिकता बिजली को दी गई है। बिजली पैदा करने तथा वितरण करने के लिए 1978-79 में 2200 करोड़ रुपये की आयोजना व्यवस्था की गई है। मैं महसूस करता हूँ कि बिजली के लिए इतनी भारी मात्रा में लागई जाने वाली पूंजी के संदर्भ में यह न्यायोचित होगा कि जिन लोगों को इस निवेशित पूंजी से लाभ पहुंचता है उनसे कुछ अंशदान प्राप्त किया जाए। इसलिए मैं उत्पावित बिजली पर 2 पैसे प्रति किलो वाट घंटे की दर से शुल्क लगाने का प्रस्ताव कर रहा हूँ। आबद्ध खपत (कैप्टिव कंजप्शन) तथा बिजली पैदा करने के लिए बिजली-घरों में सहायक संयंत्रों में इस्तेमाल के लिए पैदा की जाने वाली बिजली को इस शुल्क से मुक्त किया जा रहा है। मैं क्षति के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बिजली पर उत्पादक को शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि किसानों पर इस शुल्क का कोई बुरा असर न पड़े। इस पर प्रस्ताव से 145 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने की आशा है।

92. कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद कोयले का उत्पादन, जो 1971-72 में 720 लाख मेट्रिक टन हुआ था, 1976-77 में बढ़कर 1000 लाख मेट्रिक टन हो गया। यह राष्ट्रीयकरण के बाद राज्य द्वारा भारी मात्रा में लगाई गई पूंजी का सुपरिणाम है—हम आगे और भी पूंजी लगाते रहेंगे। यहां फिर मैं रामझता हूँ कि यह युक्तिसंगत होगा कि जो लोग इस निवेशित पूंजी से लाभ उठाते हैं उनसे कहा जाए कि वे कोयले पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का थोड़ा भार बहन करें। मैं इस संबंध में 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से उत्पाद-शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। पांच रुपये की न्यूनतम दर, देश में उत्पावित कुल कोयले के तीन-चौथाई भाग पर लागू होगी। इस प्रस्ताव से 58 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने की आशा है।

93. केन्द्रीय शुल्क उत्पाद टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत, “उन सभी वस्तुओं पर जिनका अन्यत्र उल्लेख नहीं किया गया हो,” इस समय मूल्यानुसार 2 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाया जाता है। मैं इस दर को बढ़ा कर 5 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूँ। ऐसा करते समय मैं कुछ संवेदनशील श्रेणियों की वस्तुओं अर्थात् हानिकार जीवों को मारने वाली दवाओं, खरपतवार नष्ट करने वाली दवाओं, कीट नाशक दवाओं तथा फफून्वाशक दवाओं और सामाजिक तथा पेटेंट औषधियों और दवाओं को छोड़ कर अन्य औषधियों और दवाओं, भेषजों तथा औषधियों की मध्यवर्ती वस्तुओं को इस शुल्क से पूरी तरह मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। समाचारपत्रों तथा आवधिक पत्रिकाओं को भी पूरी तरह से इस शुल्क से मुक्त किया जा रहा है। जिन छोटे निर्माताओं के यहां से पूर्ववर्ती वर्ष में निकासी किये गए उत्पाद-शुल्क लगने योग्य माल की कीमत 30 लाख रुपये से अधिक न हो उनके मामले में मौजूदा छूट मिलती रहेगी। इन प्रस्तावों से 100 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

94. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि करों के ढाँचे में नए सिरे से तोड़-मरोड़ किए बिना विकास के लिए साधन जुटाना निहायत जरूरी है, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के अन्तर्गत इस समय प्रत्येक सब पर जितना बुनियादी उत्पाद-शुल्क लिया जाता है उसके 1/20 भाग की दर से एक विशेष शुल्क लगाया जाए। ऐसा करते समय, मैं कोयला; बिजली तथा उन वस्तुओं को इस विशेष शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव रखता हूँ जिन पर उक्त टैरिफ भी मद 68 के अन्तर्गत शुल्क लगाया जाता रहा है। इस उपाय से बेसी उत्पादन पर 24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा तथा आयत की गई वस्तुओं पर लगने वाले प्रतिस्वतुलनकारी शुल्कों (काउन्टरवेलिंग ड्यूटीज) में वृद्धि हो जाने से 15 करोड़ रुपये की और रकम प्राप्त होगी।

95. अब मैं उन प्रस्तावों की ओर आता हूँ जिनके द्वारा कुछ राहतें देना चाहता हूँ। सबसे पहले, छोटे निर्माताओं को प्रोत्साहन

बेने तथा देश में उद्यमों के आधार का विस्तार करने की सरकारी नीति के अनुरूप मैं छोटे निर्मात्यों को काफी राहत देना चाहता हूँ ताकि वे बड़े एककों के साथ स्पर्धापूर्वक मुकाबला कर सकें। इस समय छोटे निर्मात्यों को दी जाने वाली तरह-तरह की शुल्क संबंधी छूट किसी एक पर्याय पर आधारित नहीं है। पिछले वर्षों में कई तदर्थ राहत दी गई है और राहत के सिद्धान्तों में काफी हद तक भिन्नता रही है। छोटे एककों की परिभाषा करने में कई तरह के मानदण्ड अपनाए गए हैं, जैसे प्रति वर्ष बी जाने वाली माल की निकासी का मूल्य, प्रति वर्ष की जाने वाली माल की निकासी की मात्रा, संयंत्र और मशीनों में लगाई गई पूंजी का मूल्य, कार्मिकों की संख्या, बिजली का उपयोग और इनमें से एक माथ दो अथवा अधिक मानदण्ड। लघु उद्योगों को दी जाने वाली राहत की पद्धति को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता को तथा आ समिति के सुझावों की ध्यान में रखते हुए मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि विनिर्दिष्ट वस्तुओं का निर्माण करने वाले उन सभी लघु एककों को, जिनके यहां से पूर्ववर्ती वर्ष में निकासी किए गए माल की कीमत 15 लाख रुपये से अधिक न हो, प्रथम 5 लाख रुपये की माल की निकासी पर वेय शुल्क से मुक्त किया जाए। यह छूट 69 मई पर लागू होगी जिनमें अन्य वस्तुओं के अलावा दवाएं, साबुन और अपमार्जक (डिटर्जेंट), पेंट और वार्निश, बिजली का घरेलू सामान, इस्पात का फर्नीचर, धातु के पात्र, वातित जल, अमारीय बनास्पती तेल, मृत्तिका-शिल्प (सिरेमिक्स) और अन्य अधिसूचित वस्तुएं भी शामिल हैं। इस प्रस्ताव से लगभग 24,000 ऐसे एककों को लाभ पहुंचेगा जिन पर इस समय उत्पाद-शुल्क संबंधी नियंत्रण लागू होता है। इससे इन एककों का प्रक्रियात्मक काम काफी कम हो जाएगा जो उन्हें करना पड़ता है। छूट के मामले में ऐसी असंगति भी दूर हो जाएगी जिसकी वजह से इस समय कई मामलों में छूट की सीमा रेखा पार करते ही राहत बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये राहत अगले वित्तीय वर्ष के शुरू से लागू होगी और इसकी वजह से 28 करोड़ रुपये के राजस्व से ह्रास होना पड़ेगा।

96. मैं शक्ति चालित पम्पों (पावर ड्रिवन पम्प) को, जिनका मुख्य रूप से कृषि में उपयोग किया जाता है, उन पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क से पूरी तरह मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रस्ताव से हर हर साल 1.5 करोड़ रुपये की हानि होगी।

97. टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले मोटर वाहनों पर इस समय जो रियायत दी जाती है उसे मैं तीन पहियों वाले प्राटो रिक्शाओं पर भी देना चाहता हूँ और उन पर लगने वाले शुल्क की दर को धीरे-धीरे प्रतिशत मूल्यानुसार घटा देने का प्रस्ताव करता हूँ। पूर्ण दूध पाउडर को उस पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क से मुक्त किया जा रहा है ताकि वह सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराया जा सके। मैं 100 लिटर और उससे कम की क्षमता वाले छोटे रेफ्रिजरेटर्स पर लगने वाले शुल्क की दर को 40 प्रतिशत मूल्यानुसार से घटा कर 30 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। इस समय, विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठानों में लगाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण तथा वातानुकूलन मशीनों (रेफ्रिजरेटिंग एण्ड एयरकंडीशनिंग मशीनरी) के पुर्जों पर 20 प्रतिशत की रियायती दर पर शुल्क लगाया जाता है। यह रियायत खिड़की तथा पैकेज टाइप के तैयार समवेत वातानुकूलन एककों (रेडी असेम्बल्ड एयरकंडीशनिंग यूनिट) के मामले में भी दी जा रही है, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर छोटे औद्योगिक संस्थानों द्वारा किया जाता है। पिछले साल, मैंने फिल्मों पर उत्पाद-शुल्क काफी बढ़ा दिया था। इस वृद्धि के सम्बंध में, तथा जिस रूप में फिल्म उद्योग पर उसका असर पड़ता है उसके संबंध में अनेकों अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। मैंने इस मामले पर सावधानी से विचार किया है और मैं 4,000 मीटर अथवा इससे कम लम्बी रंगीन फिल्मों पर तीसरे दर्जे के खण्ड पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क को 7,500 रुपये से घटा कर 5,000 रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ। काली और सफेद फिल्मों तथा लम्बी फिल्मों के मामले में यथोचित फेर-बदल किया जा रहा है। सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्म की पहली रिलीज की तारीख से 12 महीने के बाद घरेलू उपयोग के लिए अनुमत प्रतियों (प्रिंट) पर लगने वाले शुल्क को भी समुचित रूप से घटाया जा रहा है। कुल मिलाकर इन प्रस्तावों के अंतर्गत 3 करोड़ रुपये की राहत दी जा रही है।

98. तेल मूल्य त्रिषयक समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार चिकनाने के काम आने वाले तेलों और ग्रीसों पर लगने वाले शुल्कों की दरों के ढांचे को भी युक्तिसंगत बनाया गया है। युक्तिसंगत बनाने के इस उपाय से हर साल 63 लाख रुपये की निवल राशि प्राप्त होगी।

99. मैंने लेथिन वस्त्रों, सिगारों और कुरतों, चाय अपशिष्ट (टी वेस्ट) औद्योगिक प्रयोजनों के लिए बनास्पती उत्पादों, गैर-सेल्यूलोसी अपशिष्ट के मामलों में भी कुछ परिवर्तन किये हैं जिनका व्यौरा बजट पत्रों में दिया गया है। इन प्रस्तावों से 6 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

100. सीमा-शुल्कों के संघर्ष में आ समिति ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं उनको मैंने ध्यान में रखा है। राहत देने के एक उपाय के तौर पर और खासकर पूंजीगत लागत को कम करने के उद्देश्य से, मैं पूंजीगत उपस्कर की विनिर्दिष्ट मर्यों पर जिनका उत्पादन देश में नहीं होता, लगने वाले सीमा-शुल्कों की 40 प्रतिशत की दर को घटा कर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रस्ताव से 9 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी।

101. मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि कैपेसिटर बनाने के काम आने वाली पोलिप्रोपिलीन फिल्म और कंडेन्सर टिशू पेपर पर लगने वाले शुल्क में क्रमशः 155 प्रतिशत और 111 प्रतिशत की कमी कर दी जाए। कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करने से पारेषण में बिजली की हानि कम हो जाएगी और इस प्रकार पारेषण में होने वाली हानि को कम किए जाने से बिजली का पारेषण अधिक कुशलतापूर्वक हो सकेगा। इलेक्ट्रिकल इन्वुलेशन पेपर पर भी शुल्क कम किया जा रहा है। इन प्रस्तावों से राजस्व में लगभग 4 करोड़ रुपये की कमी हो जाएगी।

102. सिनेमेटोग्राफ मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक संघटकों और आयातित फीचर फिल्मों की कुछ विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में भी राहतें दी जा रही हैं। कुल मिलाकर इनसे राजस्व में 58 लाख रुपये की कमी होगी।

103. सीमा-शुल्क की दरों को बढ़ाने के बारे में मेरे पास एक ही प्रस्ताव है। मैं यह प्रस्ताव राजस्व बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए कर रहा हूँ। मैं पोलिएस्टर फिला-मेंट यार्न पर लगने वाले आयात शुल्क को 120 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे एक साल में लगभग 6.4 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

104. सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क संबंधी मेरे प्रस्तावों, से कुल मिलाकर, 1978-79 में 499 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

105. अपने प्रस्तावों के पीछे मैंने जो राजकोषीय नीति अपनाई है उसका उद्देश्य हमारी अर्थव्यवस्था में नई विस्तारकारी प्रेरक शक्तियों को पैदा करने के लिए आया और विदेशी मुद्रा की अनुकूल परिस्थिति का लाभ उठाना है। सरकारी पूंजी-निवेश में भारी वृद्धि करना इस नीति का एक तत्व है। राजकोषीय नीति को पुष्ट करने के लिए मौद्रिक नीति का भी सहारा लिया जाना चाहिए।

106. सदन को याद होगा कि सरकार ने 1974 में बैंकों की व्याज संबंधी आग्र पर कर लगाया था। सम्मानित सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि अब कीमतें काफी स्थिर हो गई हैं और उत्पादक पूंजी निवेश को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता है इसलिए अब हम कर के लिए कोई आर्थिक अतिव्यय नहीं रहा है। इसलिए मैं व्याज-कर को तत्काल वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ। मौद्रिक अभिप्राय से इस राजकोषीय रियायत के फलस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक आज के दिन बाब में व्याज दर के ढांचे में आवश्यक समायोजन की घोषणा करेगा।

107. वर्ष 1978-79 के बजट अनुमानों में व्याज-कर के रूप में 130 करोड़ रुपए की राशि को जमा खाते रखा गया है। चूंकि जनवरी और फरवरी 1978 के महीनों का व्याज-कर आगामी वर्ष में देय होगा इसलिए राजस्व में वास्तविक हानि 108 करोड़ रुपए की होगी।

108. संक्षेप में, अतिरिक्त साधन जुटाने के मेरे प्रयत्नों के फलस्वरूप 1978-79 में 549.5 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी, जिसमें से 499 करोड़ रुपए संघ उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क से, 25.5 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष करों से और 25 करोड़ रुपए अनिवार्य जमा के रूप में प्राप्त होंगे। इसमें से राज्यों का हिस्सा 95.5 करोड़ रुपए और केन्द्र का हिस्सा 454 करोड़ रुपए का होगा। व्याज-कर की समाप्ति के साथ, केन्द्र को प्राप्त होने वाले निवल अतिरिक्त साधन 346 करोड़ रुपए के होंगे।

109. अतिरिक्त साधन जुटाने के मेरे इन प्रयत्नों के बावजूद भी मैं बजट में 1050 करोड़ रुपए का घाटा उसके लिए कोई व्यवस्था किए बिना छोड़ रहा हूं। यह राशि सरकारी सोने की बिक्री से प्राप्त होने वाली रकमों के कारण कम हो आयेगी। सम्मानित सदस्य स्वयं समझ लेंगे कि मैंने किस बजह से इस राशि का अनुमान लगाने का प्रयास नहीं किया है। लेकिन सम्मानित सदस्यों की तरह मेरा भी यही मत है कि हमारी वर्तमान परिस्थितियों में हमारे संचित सोने के कुछ भाग को मोने की तस्करी की पुनरावृत्ति को रोकने के अलावा, बजट संबंधी लेने-देने के विस्तारकारी प्रभाव को कम करने के लिए उपयोग में लाना उचित है। इसी तर्क के आधार पर हम आयोजना और निवेश पर किए जाने वाले अधिक परिश्रमों के विस्तारकारी प्रभाव को निष्फल करने के उद्देश्य से अपनी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित तिथि के कुछ भाग का इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक हैं, और मुझे पक्का विश्वास है कि आगामी वर्ष में, आयात को उदार बनाने के लिए प्रारम्भ किए गए उपायों से और पूंजी-निवेश के बड़े कार्यक्रम से, जो हम अब शुरू करने का प्रस्ताव करते हैं, हमारी विदेशी मुद्रा प्रारक्षित तिथि में से काफी बड़ी रकम उपयोग में लाई जा सकेगी। इन दोनों बातों के साथ-साथ ऋण के संबंध में बराबर सतर्कता बरतने से मुद्रा उपलब्धि की निवल वृद्धि को निरापद स्तर तक सीमित रखा जा सकेगा।

110. मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि परिणामी मुद्रा-विस्तार से कोई मुद्रास्फीतिकारी बचाव खासतौर से इसलिए पैदा नहीं होंगे क्योंकि इस समय हमारे पास खाद्यान्न का भारी भंडार है और आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का आयात करने की हमारे में काफी ज्यादा क्षमता है। सरकारी खरीद और वितरण की प्रणाली के जरिए पूर्ति प्रबंध में और ऋण तथा मुद्रा नीति के जरिये मांग-प्रबंध में हमने जो अनुभव प्राप्त किया है और जो तरीके ईजाद किए हैं उनको सहायता से भी हम इन दबावों पर काबू पा सकते हैं।

111. अंत में, मैं आपको संक्षेप में यह बतलाना चाहूंगा कि मैं इस बजट के जरिये क्या प्राप्त करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य, एक ऐसी प्रक्रिया को चालू कर देना है जिससे खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन और रोजगार में बराबर वृद्धि होती चली जाए। पूंजी निवेश में सरकारी व्यय का कार्यक्रम वह प्रमुख साधन है जिसके द्वारा मैं यह उद्देश्य पूरा करना चाहता हूं। आधारभूत सुविधाओं के निवेश व्यय में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की जा रही है ताकि आगे विकास के मार्ग में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएं और सामान्य आर्थिक वातावरण में सुधार हो। इसी कारण मेरे लिए यह आवश्यक हो गया है कि मैं पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त साधन जुटाने का जिम्मा लूं। इसके साथ ही, मैंने कृषि और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकतानुसार प्रोत्साहन और कर संबंधी रियायतें देने में भी कोई कसर नहीं रखी है।

112. देश की आर्थिक स्थिति इस समय एक साहसपूर्ण कदम आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत अनुकूल है। यह बजट एक ऐसा ही कदम है।

Budget 1978-79

Speech of Minister of Finance

28th February, 1978

PART B

62. The gap of Rs. 1396 crores is clearly a very substantial gap and places on my shoulders a difficult and challenging responsibility to find ways and means of bridging the gap. I have already enumerated a number of favourable factors in the national economy which give us the necessary strength and opportunity to manage the economy even with a large though reasonable deficit without creating inflationary condition. However, prudence would require that the deficit, no matter how reasonable, should be kept as low as possible and it is, therefore, necessary to mobilise additional resources to the maximum extent possible. I am sure that the nation will willingly make a substantial contribution towards the fulfilment of a national Plan of a magnitude which will enable us to reach our objectives at a faster pace.

63. In making my proposals for resource mobilisation I have borne in mind the salutary principles of tax policy which have been laid down in the Economic Policy Resolution of the Janata Party issued in November, 1977. These principles bear repetition.

"We believe that the taxation policy of the Government must keep in mind five considerations:

(1) Increased public investment expenditure must necessitate increased public income. The people of the country, therefore, have to accept the burden of higher taxation needed for investment in the future.

(2) Taxation policy must simultaneously aim at redistributive justice and must take into consideration the capacity to pay.

(3) Taxes should be easy to collect and it should be easy for the taxpayer to know what he has to pay. There is urgent need for the simplification and rationalisation of the tax administration.

(4) Taxes must have an in-built growth potential and inherent buoyancy.

(5) Taxation policy must aim at stimulating national growth and must encourage production and savings."

64. I have had the advantage also of receiving advice from all sections of society and from all parts of the country. In addition I have received two important reports—the interim report of the Chokshi Committee on Direct Taxes and the final report of the Jha Committee on Indirect Taxes. These reports contain a number of valuable suggestions and I have given them respectful consideration.

65. Before I come to my taxation proposals I would like to make some important policy announcements which have a bearing on the budgetary position.

66. The demonetisation of high denomination bank notes was a step primarily aimed at controlling illegal transactions. It is a part of a series of measures which Government has taken and is determined to take against anti-social elements. Despite the utmost vigilance of the Customs authorities and considerable seizures and confiscations of smuggled gold, it is an unfortunate and distressing fact that gold smuggling has to some degree continued. The substantial difference between Indian gold prices and international gold prices has served as a temptation to smugglers. Gold smuggling is not only illegal but has helped to sustain black money operations and foreign exchange racketeering. It is, therefore, necessary for us to think of economic measures in addition to preventive measures to tackle this evil of gold smuggling. We have given very careful thought to the question and have decided to commence the sale of gold from the stocks held by Government. The details of the scheme are being worked out and will be announced shortly.

67. There is an excellent market for Indian gold jewellery abroad which would not only enable us to earn a significant amount of foreign exchange but also gainfully employ the undoubted craftsmanship of Indian jewellers. Hitherto the export of gold jewellery has been inhibited by the high local price of gold, restrictions placed on such exports and the complex and cumbersome bonding procedures. Government have, therefore, decided to introduce a simplified scheme for the encouragement of the export of gold jewellery. Such exports will be facilitated either by allowing importation of gold or by the sale of Government gold stocks at international prices. The details of the scheme will be announced very shortly.

68. Members will recollect that the Janata Party manifesto had contained a promise that the question of removing sales tax and octroi duties would be duly considered by the Government. I have had a series of discussions with the Chief Ministers and Finance Ministers of the States to achieve this desirable objective. The total revenue from sales tax is of the order of Rs. 2500 crores, and it is growing steadily. It constitutes the main source of revenue of the States. The Chief Ministers of the States have generally showed a lack of enthusiasm for the abolition of the sales tax. In view of the attitude of the States and since sales tax is a State subject, the task of persuading the States to give up sales tax calls for persistence and patience. It certainly cannot be regarded as something which can be accomplished in the immediate future.

69. The octroi duty, however, stands on a different footing. The revenue from octroi duty is of the order of Rs. 250 crores. There has been a long standing demand for the removal of this obnoxious levy which causes great inconvenience to trade and the transport industry. All committees which have gone into the subject have unanimously proposed its abolition. Studies have also revealed that the cost of collection of the octroi duty is unduly high. There can be no two opinions that the removal of octroi duty will be widely welcomed since its abolition will assist the orderly and healthy growth of the transport system in the country and will considerably reduce freight costs. I, therefore, propose to request the State Governments to introduce suitable legislation for the removal of octroi. The octroi revenues are at present going to the local authorities. Quite understandably they will seek from the State Governments a reimbursement for the loss of revenue and in turn the State Governments will no doubt claim a measure of compensation from the Centre. We shall hold discussions with the State Governments for finding a satisfactory solution.

70. I have now to say a few words on behalf of my colleague the Minister of Communications. The upward revision of emoluments of employees in the past few years has resulted in substantial increase in the expenditure of the Postal Branch of the Posts and Telegraphs Department which is highly labour intensive. The revenues have not, however, kept pace with the expenditure and the cost of various postal services exceed the revenues earned. Consequently, The Postal Branch has been incurring a deficit which is estimated at about Rs. 23 crores in the current year. While there is justification for increasing the tariffs for most of the postal services, it is proposed to touch only those services which will not affect the common man, particularly in the rural areas. A memorandum showing the proposed changes in the postal tariffs is being circulated along with the Budget papers.

71. The tariff revisions, which will be given effect to from a date to be notified by the Government after the Finance Bill is passed, are estimated to bring in an additional revenue of Rs. 13.73 crores per annum. The yield during 1978-79 is estimated at Rs. 11.44 crores. The results of the tariff revisions have been accounted for in estimating the internal resources of the Posts and Telegraphs.

72. I shall now deal with my proposals in the sphere of direct taxes.

73. I have kept in view the fact that a substantial increase in investment has necessarily to be backed by increased efforts at mobilisation of savings. My proposals in the field of direct taxes are accordingly designed to promote larger savings; to curb extravagant and wasteful expenditure in businesses and professions; and to channelise funds for stimulating growth and production. I have also sought to

provide some tax relief in selected areas with a view to encouraging larger investment in desired directions.

74. In order to mobilise additional resources in the form of savings, I propose to raise the rates of compulsory deposit in the case of income-tax payers. While taxpayers having current income up to Rs. 15,000 will continue to enjoy immunity from the requirement of making compulsory deposit, in the case of incomes exceeding Rs. 15,000 and up to Rs. 25,000 the rate will be raised from 4 per cent to 4½ per cent. On the slab of Rs. 25,001 to Rs. 70,000, compulsory deposit is currently made at the rate of 10 per cent. I propose to split this slab into two. While the rate on the slab of Rs. 25,001 to Rs. 35,000 will be 11 per cent, the rate on the slab of Rs. 35,001 to Rs. 70,000 will be 12½ per cent. On the slab over Rs. 70,000 the rate will be raised from 12 per cent to 15 per cent. Approximately Rs. 25 crores will accrue in 1978-79 as a result of this measure.

75. I propose to liberalise the concession in respect of long-term savings through life insurance, provident fund contributions and other approved forms of saving. At present, 100 per cent of the first Rs. 4,000 of the qualifying savings, 50 per cent of the next Rs. 6,000 and 40 per cent of the balance is allowed as deduction in computing the taxable income. I propose to allow a deduction equal to 100 per cent of the first Rs. 5,000 of the qualifying savings. The quantum of deduction in respect of the next Rs. 5,000 will continue at the existing rate of 50 per cent and, in respect of the balance, at the existing rate of 40 per cent. The monetary limit for the savings qualifying for deduction under this provision is also being raised from Rs. 20,000 to Rs. 30,000. These measures will result in a revenue loss of Rs. 10 crores in a full year and Rs. 7.5 crores in 1978-79.

76. Investors understandably prefer investment which brings them a safe return, which is provided by fixed deposits in banks or shares of established companies with a good record for payment of dividends. This results in new companies not attracting adequate support. In order to stimulate such investment, I propose to give a deduction in the computation of taxable income of 50 per cent of the amount invested in equity shares of new industrial companies. The maximum investment in a year qualifying for this deduction will be limited to Rs. 10,000. This will entail a loss of Rs. 5 crores in a full year and Rs. 3.5 crores in 1978-79. I would cheerfully accept a much larger loss if it results in stimulating larger investments.

77. Last year, I had introduced a provision to exempt capital gains in cases where the sale proceeds arising from the transfer of an asset are reinvested within six months in units of the Unit Trust of India, shares of Indian companies, bank deposits and other specified assets. In order that this concession leads to the flow of investible funds into fresh ventures, I propose to provide with immediate effect that investment in shares of Indian companies will be taken into account for the purposes of exemption from capital gains tax only where the investment is made in equity shares of new industrial companies.

78. Banks allow substantial advances against the security of fixed deposits with them. Hence, taxpayers who get exemption from capital gains tax by making such deposits obtain an unduly large tax benefit without commensurate sacrifice. I have, therefore, decided that fixed deposits with banks made after today will not qualify as an eligible mode of investment for the purposes of this exemption.

79. The annual letting value of a newly constructed house is reduced for tax purposes by an amount up to Rs. 1,200 in respect of each residential unit for a period of a period of five years. With a view to providing a stimulus for construction of houses, particularly for persons in the low and middle income brackets, I propose to raise the monetary limit of Rs. 1,200 to Rs. 2,400.

80. Initial depreciation allowance is currently granted at the rate of 20 per cent on the cost of new buildings erected by employers for their low-paid employees. In order to give a greater impetus to the construction of buildings for workers, I propose to increase the rate of initial depreciation allowance from 20 per cent to 40 per cent.

81. The foreign remuneration of Indian citizens employed outside India is liable to Indian income-tax if their stay in India exceeds a specified period. As this results in avoidable hardship and discourages such persons from spending even a reasonable period or vacation in their home country, I propose to provide that Indian citizens employed outside India may stay on vacation in the country for 89 days in a year without attracting such tax liability.

82. In order to ensure that winnings from horse races are effectively brought within the tax net, I propose to provide for deduction of tax at source at the rate of 34.5 per cent from winnings in excess of Rs. 2,500. This measure would yield Rs. 4 crores in a full year and Rs. 3.5 crores in 1978-79.

83. Extravagant and socially wasteful expenditure is often incurred on advertisement, publicity and sales promotion. In order to put a curb on such expenditure at the cost of the exchequer, I propose to provide for the disallowance of a part of such expenditure in the computation of taxable profits. Where the aggregate expenditure on advertisement, publicity and sales promotion in India does not exceed 1/4 per cent of the turnover or gross receipts of the business or profession, 10 per cent of such expenditure will be disallowed in computing the taxable profits. Where such aggregate expenditure exceeds 1/4 per cent but does not exceed 1/2 per cent of the turnover or gross receipts, the disallowance will be made at the rate of 12½ per cent; and where such expenditure exceeds 1/2 per cent of the turnover or gross receipts, the disallowance will be made at the rate of 15 per cent. These provisions will not apply in cases where the aggregate expenditure on advertisement, publicity and sales promotion does not exceed Rs. 20,000 in a year. Newly established industrial concerns will also be exempted from this provision for an initial period of three years. This measure will yield Rs. 31 crores in a full year and about Rs. 25 crores in 1978-79.

84. A weighted deduction is currently allowed in the computation of taxable profits with reference to expenditure incurred by Indian companies and resident taxpayers, other than companies, on development of export markets. The weighted deduction is allowed at the rate of 150 per cent of the actual expenditure in the case of widely-held companies and at the rate of 133.3 per cent in the case of other taxpayers. While the full deduction of expenditure incurred for development of export markets is entirely justifiable, and no part of such expenditure will be disallowed under the proposed provision for disallowance of expenditure on advertisement, publicity and sales promotion, I do not see adequate justification now for continuing to subsidise such expenditure by the grant of weighted deduction. I, therefore, propose to discontinue the grant of weighted deduction in relation to such expenditure incurred after 31st March, 1978. This measure is likely to yield Rs. 10 crores in a full year and Rs. 8 crores in 1978-79.

85. In the case of a taxpayer who has previously been assessed to income-tax, advance tax becomes payable only if a notice in this behalf is issued by the Income-tax Officer. Hence, if an advance tax notice is not issued in the case of such a taxpayer, he will have no liability to pay any advance tax. On the other hand, taxpayers who have not been assessed to income-tax, are required to pay advance tax on their own on the basis of their estimated current income. To my mind, the existing legal position is clearly unsatisfactory. I, therefore, propose to provide that advance tax shall be voluntarily paid by every person if his current income exceeds the specified limit.

86. The Direct Tax Laws Committee under the chairmanship of Shri S. C. Chokshi submitted its interim report last December. The report contains a number of valuable suggestions for simplification and rationalisation of tax laws, streamlining assessment procedures, reducing the area of litigation and accelerating the disposal of appeals and references. In its report on the Central Direct Taxes Administration, the Administrative Reforms Commission had recommended that amendments to the tax laws should not be rushed through the annual Finance Bill, which needs to be passed before a prescribed date, but made through separate bills whose provisions can be considered in detail. Pursuant to this recommendation, I

propose to introduce separate legislation as early as possible to give effect to the main recommendations of the Chokshi Committee which are acceptable to the Government. In the meanwhile, a few changes recommended by the committee, such as deduction of tax at source from race winnings and voluntary payment of advance tax, which could be easily incorporated in the tax law, have been introduced through the Finance Bill.

87. The exemption limit for estate duty, which is Rs. 50,000 was fixed as long ago as 1958. As this exemption limit is unduly low, I propose to raise it to Rs. 1 lakh. Since, in this matter, we can move only with the concurrence of the State Legislatures, a Bill for implementing this proposal, and certain other proposals in relation to estate duty, will be introduced later this year.

88. The total additional revenue from the various measures enumerated by me will yield Rs. 30 crores in a full year and Rs. 25.5 crores during 1978-79. Besides, additional resources of about Rs. 25 crores will accrue in the form of compulsory deposits in the financial year 1978-79.

89. May I now turn to my proposals relating to indirect taxes? Our basic national problem, and indeed this is a problem facing all developing countries, is that the base for direct taxes is extremely narrow and the vast funds required for national development cannot, therefore, be raised, at our present stage of development, from direct taxes alone. While framing the proposals relating to indirect taxes, however, I have in mind the need to protect small scale industry and to minimise the hardship to the poor and the middle class consumers.

90. Hon'ble Members are aware that Government had appointed a committee, to review the existing structure of the indirect tax system, under the chairmanship of Shri L. K. Jha. The committee has now submitted its final report. Amongst the important recommendations made by the committee are restructuring of the pattern of central excise and customs duties, measures to assist the small scale sector, the general reorientation of the tariff to make it income-elastic and the desirability of introducing a value added tax so as to avoid the cascading effect of taxes on raw materials and components of finished products. The committee has also made some recommendations regarding indirect taxes levied by State Governments and local authorities. Government has been examining all these recommendations with the care which they deserve. In my last Budget, I had in fact accepted and implemented a few of the recommendations which were available to us in the interim report of the committee. The proposals which I am making today incorporate some of the recommendations made in the final report. Other recommendations which involve a major restructuring of the system would require further study.

91. In the Plan outlay the topmost priority has been accorded to power. The Plan provision for power generation and distribution is of the order of Rs. 2,200 crores in 1978-79. I feel that with our enormous investments in power, there is ample justification for claiming a contribution from those who benefit from these investments. I am, therefore, proposing to levy a duty of 2 paise per kilowatt-hour on electricity generated. Electricity generated for captive consumption, as well as that used in the auxiliary plants in the generating stations for the generation of electricity, is being exempted. I also propose to give a rebate of the duty to the producer in respect of electricity used for agricultural purposes so that agriculturists are not affected. This levy is expected to yield a revenue of Rs. 145 crores.

92. After the nationalisation of the coal mines, coal production has increased from about 72 million tonnes in 1971-72 to about 100 million tonnes in 1976-77. This is the result of enormous investments made by the State after nationalisation, which we will continue to make. I think, justifiably be called upon to bear a small levy of central excise duty on coal. I propose to fix this at rates varying from Rs. 5 to Rs. 10 per tonne. The lowest rate of Rs. 5 would cover three-fourths of the coal produced in the country. This measure is expected to yield a revenue of Rs. 58 crores.

93. Under Item 68 of the Central excise tariff, the rate of duty leviable on "all articles, not elsewhere specified" is at present 2 per cent *ad valorem*. I propose to raise this to the level of 5 per cent *ad valorem*. While doing so, I propose to exempt some sensitive categories of goods, namely, pesticides, weedicides, insecticides and fungicides, drugs and medicines other than proprietary or patent drugs and medicines, pharmaceuticals and drug intermediates, from the whole of the duty leviable under this item. Newspapers and periodicals are also being exempted completely. The existing exemption in respect of small manufacturers whose clearance of excisable goods does not exceed Rs. 30 lakhs in the preceding year will continue. These proposals will yield a revenue of Rs. 100 crores.

94. In view of the paramount need for mobilising resources for development without creating fresh distortions in the tax structure I propose to levy a special duty at the rate of 1/20th of the basic excise duties presently collected on each item in the Central excise tariff. In doing so, I propose to exempt coal, electricity and goods which are assessed under Item 68 of the tariff. This measure will result in an additional revenue of Rs. 214 crores on indigenous production and a sum of Rs. 15 crores by way of increase in countervailing duties on imports.

95. May I now turn to the reliefs which I propose to give. First of all, consistent with the policy of the Government to encourage the small manufacturer and to widen the entrepreneurial base in the country, I propose to provide sufficient relief to small manufacturers so as to enable them to compete successfully with larger units. The duty exemptions at present available to small scale manufacturers are not based on any one pattern. Over the course of years, a number of *ad hoc* concessions have been given and the principles of relief have varied very widely. In defining the small units, a variety of formulae have been adopted, such as, value of clearances per annum, quantity of clearances per annum, value of capital investment on plant and machinery, number of workers, use of power, and a combination of two or more of these criteria. Keeping in view the need for rationalising the pattern of relief to small industries and bearing in mind the recommendation made by the Jha Committee, I propose to exempt all small scale units manufacturing specified goods, whose clearances in the preceding year did not exceed Rs. 15 lakhs, from the duty payable on the first clearance of Rs. 5 lakhs. The exemption will cover 69 items including, amongst others medicines, soap and detergents, paints and varnishes, household electrical goods, steel furniture, metal containers, aerated waters, vegetable non-essential oils, ceramics and other items notified. This measure will benefit about 24,000 units currently under excise control. It will reduce considerably the procedural requirements which these units are required to follow. It will also remove the anomaly, under which relief is presently lost totally in many cases, the moment the threshold limits of exemption are crossed. This relief will be effective from the beginning of the next financial year and involve a revenue sacrifice of Rs. 28 crores.

96. I propose to exempt power-driven pumps mainly used in agriculture from the whole of the excise duty leviable thereon. The measure will involve a loss of Rs. 1.5 crores per annum.

97. I also propose to extend the concession currently available to motor-vehicles used as taxis to 3-wheeler auto-rickshaws as well, by reducing the rate of duty leviable on the latter by 2½ per cent *ad valorem*. Whole milk powder is being exempted from payment of the duty leviable thereon in an effort to make available this commodity at a cheaper rate. I also propose to reduce the rate of duty leviable on small refrigerators of a capacity of 100 litres and less from 40 per cent *ad valorem* to 30 per cent *ad valorem*. At present parts of refrigerating and air-conditioning machinery required for installation in specified establishments are assessed at a concessional rate of 20 per cent. This concession is being extended to ready assembled airconditioning units of the window and package type, generally used by smaller industrial installations. Last year I had raised the excise duty on films substantially. There have been a number of representations against the increase and the manner in which it affects the industry. I have carefully considered the matter and propose to reduce the excise duty leviable from Rs. 7,500 to Rs. 5,000 on the third dozen slab of colour prints, of length 4,000 metres or less. Suitable adjustments

are being made in the case of black and white films as well as longer films. Duty on prints cleared for home consumption after twelve months from the date of first release of the film for public exhibition is also being reduced suitably. These proposals together imply a relief of about Rs. 3 crores.

98. In pursuance of Government's decisions on the Oil Prices Committee's Report, the tariff structure relating to lubricating oils and greases has also been rationalised. This measure of rationalisation will yield Rs. 63 lakhs net in a year.

99. I have also carried out some modifications in respect of coated fabrics, cigars and cheroots, tea waste, vegetable products for industrial purposes and non-cellulosic wastes, the details of which are given in the Budget documents. These proposals will yield a revenue of Rs. 6 crores.

100. I have taken note of the significant suggestions in regard to customs duties made by the Jha Committee. As a measure of relief and particularly with a view to bringing down capital costs, I propose to reduce the customs duties on specified items of capital equipment not produced indigenously from the current level of 40 per cent to 25 per cent. The revenue loss will be of the order of Rs. 9 crores.

101. I also propose to reduce the duty leviable on condenser tissue paper and polypropylene film used in the manufacture of capacitors, by 111 per cent and 155 per cent respectively. Use of capacitors will reduce transmission losses and will thus help the more efficient transmission of power. Duty on electrical insulation paper is also being reduced. These proposals will involve a revenue sacrifice of about Rs. 4 crores.

102. Certain reliefs are also being given in respect of specified items of cinematograph machinery, electronic components and imported feature films. These together will involve a revenue sacrifice of Rs. 58 lakhs.

103. I have only one proposal for upward modification of the customs tariff, not so much as a measure of raising revenue but as a measure of protection to Indian industry. I propose to increase the import duty on polyester filament yarn from 120 per cent to 200 per cent and *ad valorem*. This will yield about Rs. 6.4 crores in a year.

104. My proposals for Customs and Central excise duties put together will yield an additional revenue of Rs. 499 crores for 1978-79.

105. The fiscal strategy underlying my proposals seeks to take advantage of the favourable food and foreign exchange situation for generating fresh expansionary impulses in our economy. The big step up in public investment is one element of this strategy. Monetary policy must also be used to reinforce fiscal policy.

106. The House will recollect that Government had imposed a tax in 1974 on interest income of banks. Hon'ble Members will agree with me that, now that prices are reasonably stable and there is urgent need to stimulate productive investment, this tax has lost its economic justification. I propose, therefore, to withdraw the interest-tax with immediate effect. As a sequel to this fiscal concession with a monetary intent, the Reserve Bank of India will be announcing later in the day the realignment of the interest rate structure.

107. The Budget Estimates for 1978-79 have taken credit for an amount of Rs. 130 crores on account of interest-tax. Since the interest-tax for the months of January and February, 1978 will be payable in the coming year, the actual loss of revenue will be of the order of Rs. 108 crores.

108. To sum up, my efforts at mobilisation of additional resources will yield in 1978-79 Rs. 549.5 crores, of which Rs. 499 crores will be from Union excise and customs duties, Rs. 25.5 crores from direct taxes and Rs. 25 crores as compulsory deposits. Out of this, the States' share will be Rs. 95.5 crores and the Centre's share Rs. 454 crores. With the withdrawal of interest-tax, the net additional resources accruing to the Centre will be Rs. 346 crores.

109. Despite the effort which I have made at raising additional resources, I am leaving an uncovered budgetary gap

of Rs. 1,050 crores. This figure will be reduced by the receipts from sales of Government gold. For reasons which Hon'ble Members will appreciate I shall not attempt to estimate this figure. But I should share with Hon'ble Members the view I hold that, apart from preventing any resurgence of gold smuggling, it is also justifiable, in our present circumstances, to utilise a part of our accumulated gold to reduce the expansionary effect of budgetary transactions. It is on the same reasoning that we have been anxious to deploy a part of our foreign exchange reserves to offset the expansionary impact of larger Plan and investment outlays; and I am confident that in the coming year the steps initiated to liberalise imports and the major investment programme that we now propose to undertake, will lead to a significant draw down of foreign exchange reserves. These two factors combined with continued vigilance regarding credit should limit the net increase in money supply to safe levels.

110. I am satisfied that the resultant monetary expansion will not lead to any inflationary pressures particularly in view of the large stock of foodgrains and the much greater ability that we have at present to import essential consumer goods.

The experience we have gained and the instruments we have forged in supply management through procurement and public distribution and demand management through credit and monetary policy should also enable us to contain such pressures.

111. In conclusion let me summarise what I seek to achieve through this Budget. My goal is to set in motion a process of sustained increase in output and employment, particularly in the rural areas. The programme of government expenditure on investment is the main instrument I wish to use to attain this goal. Investment expenditure in infrastructure facilities is being raised steeply so that bottlenecks coming in the way of further growth are removed and there is an improvement in the general economic climate. This has made it necessary for me to undertake sizable additional resource mobilisation. At the same time I have not hesitated to offer incentives and tax concessions where these are called for to promote investment in agriculture and industry.

112. The economic situation of the country is exceptionally favourable at present for a bold step forward. This Budget is such a step.